सूर्योदय - 06:26
सूर्यास्त - 05 : 44

अधिकतम तापमान 32.0°
न्यूनतम तापमान 19.0°

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

ओपन सर्च

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in
Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 350 नई दिल्ली, मंगलवार 24 नवम्बर-2026
नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित
` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

भारत और नेपाल रिश्तों में नई मजबूती

हवाई, रेलवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन और हाइड्रोपावर पर लिए कई फैसले

नई दिल्ली.ओपन सर्च



दोनों देशों ने हवाई संपर्क, रेलवे नेटवर्क, पेट्रोलियम अवसंरचना और जलविद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष दिया जोर, दोनों नेताओं ने नागर विमानन क्षेत्र में चल रही वार्ताओं की समीक्षा की और संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने सोमवार को दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों देशों ने हवाई संपर्क, रेलवे नेटवर्क, पेट्रोलियम अवसंरचना और जलविद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

दोनों नेताओं ने नागर विमानन क्षेत्र में चल रही वार्ताओं की समीक्षा की और संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तहत वर्तमान काठमांडू-भैरहवा-लखनऊ (बी345) हवाई मार्ग, जो अभी एकतरफा है, उसे दोतरफा बनाया जाएगा। इसके लिए दोनों पक्ष तकनीकी स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के ट्रांजिट व्यापार के लिए एक नई सुविधा की घोषणा करते हुए कहा कि नेपाल को दीनदयाल पोर्ट (कांडला, गुजरात) के माध्यम से अतिरिक्त समुद्री पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद पारादीप बंदरगाह (ओडिशा) का उपयोग भी नेपाल के लिए खोला जाएगा। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने सीमा पार संपर्क और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के महत्व पर बल दिया। इसके तहत नई रेलवे लाइनों, पुलों, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) और पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सरयू-कमला एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई, जो अयोध्या और जनकपुर को जोड़ती है। माना जा रहा है कि यह रेल सेवा न केवल आवागमन को आसान बनाएगी बल्कि रामायण सर्किट के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगी तथा भारत-नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करेगी।

दोनों देशों ने बौद्ध और शिव-शक्ति धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए इसी तरह के अन्य संपर्क मार्गों की संभावनाओं का भी अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की। रेल संपर्क के क्षेत्र में दोनों पक्षों ने प्रस्तावित रक्सौल-काठमांडू विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए फील्ड लोकेशन सर्वे पूरा होने की घोषणा की।

साथ ही नेपाल की ईस्ट-वेस्ट रेलवे परियोजना के विकास में सहयोग करने पर भी सहमति बनी। सीमा संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए भारत के धारचूला और नेपाल के दारचूला के बीच एक नए मोटर योग्य पुल का उद्घाटन किया गया, जिससे पश्चिमी नेपाल और भारत के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा।

नेपाल को 15 हजार करोड़ की विकास सहायता, ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की ऋण सुविधा देगा भारत

भारत ने पड़ोसी प्रथम की अपनी नीति पर चलते हुए नेपाल को विकास परियोजनाओं के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है जिसमें आपदा के बाद पुनर्निर्माण और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता तथा ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में इस पर सहमति बनी।

बिहार विधान परिषद के आठ नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ



विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय ने सभी आठ नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, लेसी सिंह तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे

ओपन सर्च. संवाददाता

पटना। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से नवनिर्वाचित आठ सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को परिषद सभागार में आयोजित किया गया। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय ने सभी आठ नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, लेसी सिंह तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले जदयू के नीरज कुमार ने शपथ ली। इसके बाद दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अनिल कुमार झा सहित अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली।

इनमें एनके यादव, डॉ. संजीव कुमार और सुरेश प्रसाद राय सहित आठ सदस्य शामिल रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दो नवनिर्वाचित सदस्यों राहुल राज और वंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण करने वाले सभी सदस्यों को उनकी शुभकामनाएँ हैं, लेकिन दो व्यक्तियों को लेकर उनकी आपत्ति बरकरार है।

तेजस्वी यादव ने कहा, हमारे लोग वकीलों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही एक बार फिर हम लोग शिकायत लेकर चेयरमैन साहब के पास जाएंगे। पटना हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। कानून और नियमावली के हिसाब से इन दोनों की सदस्यता जाएगी। वहीं, शपथ ग्रहण के बाद जदयू नेता नीरज कुमार ने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण दिन बताया। उन्होंने कहा कि उच्च सदन में शपथ लेने का अवसर मिलना उनके लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि यह भी उनके लिए विशेष गौरव की बात है कि उनके गुरुदेव प्रोफेसर रामवचन राय आज विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हैं। नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के प्रति आभार जताया। साथ ही उन मतदाताओं का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी।

उन्होंने कहा कि 'सात निश्चय-3' के तहत विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में वह विधान परिषद में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। इधर, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शपथ ग्रहण को संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया।

पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग' करने को मंजूरी, 9 दिसंबर को विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव



कोलकाता.एजेंसी

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य का नाम 'पश्चिम बंगाल' से बदलकर 'पश्चिम बंग' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया, 'इस संबंध में एक प्रस्ताव को एक बैठक में मंजूरी दी गई है।

इसी प्रस्ताव को 9 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा।' उन्होंने यह भी कहा कि राज्य विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद, इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 से 14 दिसंबर तक चलेगा। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, प्रशासनिक कारणों से राज्य का नाम बदलने का विचार काफी समय से चल रहा है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की बैठकों में, राज्यों के प्रतिनिधियों को अंग्रेजी वर्णमाला (अल्फाबेटिकल ऑर्डर) के क्रम में बोलने का मौका दिया जाता है। इस वजह से, ऐसी सभी बैठकों में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों को हमेशा सबसे अंत में बोलने का अवसर मिलता था। पिछले महीने, पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने दावा किया था कि राज्य सरकार जल्द ही एक विधेयक पेश करेगी, जिसके तहत 'पश्चिम बंगाल' का नाम बदलकर सभी भाषाओं में 'पश्चिम बंग' कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की कोशिश सबसे पहले 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय ज्योति बसु के नेतृत्व वाली वाम मोर्चे की सरकार ने शुरू की थी।

मुख्यमंत्री साय ने धनोरा में दी 132.69 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

आदिवासी समाज ने पारंपरिक साफा बांधकर किया मुख्यमंत्री साय आत्मीय स्वागत

ओपन सर्च. संवाददाता



- **मुख्यमंत्री ने 2.50 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया लोकार्पण, 56 गांवों के 56 हजार ग्रामीणों को मिलेगा लाभ**
- **बिहान की दीदियां संभालेंगी धान के प्रसंस्करण से लेकर विपणन तक की जिम्मेदारी, ग्रामीण महिलाओं को मिलेंगे स्वरोजगार के नए अवसर**

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कोण्डागांव जिले के ग्राम धनोरा में विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही किसानों की समृद्धि, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने जिले में 132 करोड़ 69 लाख 43 हजार रुपये की लागत के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया तथा सुदूर वनांचल के किसानों की उपज को नई बाजार पहचान दिलाने के लिए 'कोंडानार प्रीमियम राइस' ब्रांड का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कोनगुड़ परगना के प्रमुख आराध्य पेन खण्डा मुदिया के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे गांवों और वहां रहने वाले प्रत्येक परिवार तक पहुंचे। दूरस्थ वनांचलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के नए अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों, परंपरागत कृषि पद्धतियों और ग्रामीण प्रतिभाओं को नए अवसरों से जोड़कर ही समृद्ध और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री साय ने धनोरा में 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया।

इस स्वास्थ्य केंद्र से धनोरा सहित आसपास के 56 गांवों के लगभग 56 हजार ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अब क्षेत्र के लोगों को सामान्य बीमारियों के उपचार, स्वास्थ्य जांच और अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के लिए दूर-दराज के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

'दो महापुरुष, एक संकल्प' कार्यक्रम का हुआ आयोजन, दिल्ली सीएम व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली.ओपन सर्च



देहदानी श्री मांगेराम गर्ग सेवा समिति द्वारा आयोजित 'दो महापुरुष, एक संकल्प' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने शिरकत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दो महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विशेष आयोजन दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम गर्ग की 90वीं जयंती तथा श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक अशोक सिंघल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया।

कार्यक्रम में दोनों महापुरुषों के योगदान को स्मरण किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मांगेराम गर्ग ने जनसंघ के समय से ही संगठन को सशक्त बनाने और समाजसेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। वहीं, अशोक सिंघल ने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से करोड़ों रामभक्तों को एकजुट कर देश में सांस्कृतिक जागरण को एक नई दिशा प्रदान की। वक्ताओं ने कहा कि दोनों महान विभूतियों का जीवन सेवा, त्याग, संगठन शक्ति और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। आज दिल्ली इन्हीं महान आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनसेवा के दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। इस श्रद्धांजलि सभा में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद कमलजीत सहरावत, भाजपा दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पीएम मोदी 2029 में फिर नजर आएंगे, राहुल गांधी सपने देखते रहें : नितिन नवीन

नई दिल्ली.एजेंसी



नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बार-बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन देश की जनता का समर्थन भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित 'सेव डेमोक्रेसी, रिमूव एनार्की' महा पदयात्रा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे, 2029 में लाल किले की प्राचीर से फिर नजर आएंगे। राहुल गांधी सपने देखते रहिए, देश का युवा, किसान, महिला, मजदूर और हर वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है।

नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बार-बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन देश की जनता का समर्थन भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। करीमनगर की जनता ने भी अपने आशीर्वाद के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग पूरी ताकत लगाने के बावजूद एक रामलीला मैदान नहीं भर पाए, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 200 से अधिक स्थानों पर रामलीला मैदान से कहीं ज्यादा लोगों को एकत्र किया। विपक्ष ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा को लोकतंत्र का आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि जो लोग अपने हाथों में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि संविधान केवल हाथ में रखने की चीज नहीं है, बल्कि हमारे दिल में है।

राहुल गांधी और विपक्षी दल जुबान से संविधान की बात करते हैं, जबकि भाजपा संविधान को पूजती है और सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है। नितिन नवीन ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने 13 करोड़ लोगों के वोट चोरी होने का दावा किया था। उन्होंने पूछा कि तीन करोड़ लोगों को मतदाता सूची में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? छह करोड़ से अधिक लोग अपना स्थान बदल चुके हैं। तेलंगाना में भी लाखों लोगों ने अपने वोट दूसरी जगह स्थानांतरित कराए हैं।

भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का ट्रायल रन मई 2027 में सूरत-बिलिमोरा सेक्शन पर होगा

नई दिल्ली.ओपन सर्च



केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव के करीब पहुंच गई है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के सूरत-बिलिमोरा सेक्शन पर मई 2027 से ट्रायल रन शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्री के अनुसार, 50 किलोमीटर लंबा सूरत-बिलिमोरा सेक्शन देश के पहले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला हिस्सा होगा, जिस पर बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जाएगा। यह परियोजना भारत की हाई-स्पीड रेल यात्रा की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस सेक्शन पर सिग्नलिंग का कार्य अगले वर्ष जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि विद्युतीकरण का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। 20 नवंबर को इस सेक्शन की अप और डाउन दोनों एलिवेटेड लाइनों पर ओवरहेड उपकरणों को सफलतापूर्वक चार्ज भी किया गया। वैष्णव ने कहा कि पूरे कॉरिडोर में 2×25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है और बिलिमोरा ट्रैक्शन सब-स्टेशन पर स्थापना कार्य भी पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। अहमदाबाद-वापी सेक्शन को 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि सेवाओं को 2029 तक ठाणे तक विस्तार देने की योजना है। शुरुआती ट्रायल बी-28 ट्रेनसेट के साथ किए जाएंगे, जिसे 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है।

सीएम धामी ने आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेले एवं विकास प्रदर्शनी का विधिवत किया शुभारंभ

ओपन सर्च/ओ पी उनियाल



बैकुंठ चतुर्दशी मेला केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी लोकसंस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है : मुख्यमंत्री पुष्कर धामी

देहरादून। श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेले एवं विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी लोकसंस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ की सीवर लाइन परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगभग 650 करोड़ की लागत से एनआईटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। क्षेत्र में पैरामेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

नगर में आधुनिक बस स्टैंड एवं पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। कोटद्वार-पौड़ी-श्रीनगर सड़क के दो लेन चौड़ीकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने ढोल-दमाऊं, पुष्पवर्षा एवं जयकारों के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मेले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर स्थानीय उत्पादों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सिलबट्टे से पहाड़ी नमक भी पीसा। मुख्यमंत्री ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

उन्होंने कहा कि बेस अस्पताल श्रीनगर में लगभग 25 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में लगभग नौ करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, सड़क एवं नाली निर्माण तथा पार्कों के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से देहरादून के लिए जल्द हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।

पंचायतों और नगर निकायों के अधिकारों के हस्तांतरण, वित्तीय स्थिरता व प्रभावी सेवा वितरण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विकसित भारत-2047 की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब देश का हर गांव और शहर का हर वार्ड आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगा। पंचायतों और नगर निकायों को केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आय के नए स्त्रोत विकसित करने होंगे।

इसके लिए स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, वित्तीय प्रबंधन और जनभागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकारों को अधिकार, क्षमता और अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर आत्मनिर्भर बनाना ही इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी सोमवार को गुरुग्राम के सेक्टर-51 स्थित गुरुग्राम विश्वविद्यालय में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। पंचायतों एवं नगर निकायों को अधिकारों का हस्तांतरण, वित्तीय स्थिरता तथा प्रभावी सेवा वितरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल,स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान महानिदेशक डॉ राज नेहरू भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों एवं नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इन्हें वास्तविक रूप से सशक्त स्थानीय सरकार के रूप में विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान आवश्यकताओं से जोड़ने का काम किया है। गांव विकास की अंतिम कड़ी नहीं, बल्कि विकास का केंद्र है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की प्राथमिकताएं ही पंचायतों की कार्ययोजना का आधार बननी चाहिए। सरपंच और पार्षद लोकतंत्र की जमीनी ताकत हैं, क्योंकि वे सीधे जनता से जुड़े होते हैं और लोगों की समस्याओं को सबसे पहले समझते हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में वर्ष 2014 से पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2015 में पढ़ी-लिखी पंचायतों की व्यवस्था लागू की गई और वर्ष 2020 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। इसी प्रकार लाल डोरा मुक्त अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाया गया, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में किए गए सुधारों का उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीणों को उनके अधिकारों से जोड़ना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों और नगर निकायों की आय बढ़ाने के लिए जल संरक्षण, पानी के बिलों की वसूली तथा स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने गांवों में पानी के बिल के रूप में जितनी राशि एकत्रित की जाएगी, उतनी ही मैचिंग ग्रांट देने का निर्णय लिया है, ताकि पंचायतों की आमदनी बढ़ सके।

उन्होंने कहा कि गिरते भूजल स्तर और पानी की कमी को देखते हुए प्रत्येक जनप्रतिनिधि को जल संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी होगी। स्थानीय निकायों को अपनी आय के नए स्त्रोत तलाशने के साथ-साथ शहरों में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

कार्यक्रम में पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, फाइनेंस एवं प्लानिंग विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल, भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग के पूर्व सदस्य तथा फ्लेम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रो. मनोज कुमार पांडा, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर संजय कौशिक, प्रोफेसर एन.के बिश्नोई, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, जिला प्रशासन से पुलिस आयुक्त शिवास कविराज तथा डीसी उत्तम सिंह सहित हरियाणा तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।



गांवों और वार्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर किया जाएगा सम्मानित

मुख्यमंत्री ने पंचायतों, गांवों और वार्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांवों और वार्डों के विकास के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कर बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों एवं निकायों को सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे जनप्रतिनिधियों में अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने की भावना विकसित होगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि केवल पदाधिकारी नहीं, बल्कि परिवर्तन के वाहक हैं। उन्हें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे दोनों दिन होने वाले विचार-विमर्श में सक्रिय भागीदारी निभाएं और ऐसे व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करें, जिन्हें धरातल पर लागू कर पंचायतों एवं नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एशिया पावर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में भारत तीसरे स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है।

आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : एमडी

ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को लेकर लघु सचिवालय में एमडी शुगर मिल गोहाना अंकिता वर्मा की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। समाधान शिविर में कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई। शिविर के दौरान अंकिता वर्मा ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए तथा प्रत्येक मामले का निर्धारित समय सीमा के अंदर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। समाधान शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का



त्वरित समाधान करना है, इसलिए किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

शिविर के दौरान प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से गांव सलीमपुर माजरा से ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने, गांव गढ़ी बिंदरौली से अतिक्रमण हटवाने, गांव बैयांपुर में गंदे पानी की निकासी व नाले की सफाई करवाने, विधवा पेंशन बनवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का सर्वे करवाकर पहली किस्त जारी करवाने, गांधीनगर, गोहाना से अवैध कब्जा हटवाने, सोनीपत सेक्टर-23 में आवारा कुत्तों के बढ़ते प्रकोप की शिकायत प्राप्त हुई। अन्य मामलों में गांव सांदल खुर्द से खेतों के बीच में लगे ट्रांसफार्मर को किनारे पर लगवाने, गांव रूखी से विधवा पेंशन बनवाने, 134ए के तहत दाखिला होने पर विद्यालय द्वारा मनमाने तरीके से शुल्क वसूल करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र और पेंशन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी मामलों पर सुनवाई करते हुए एमडी अंकिता वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द इन शिकायतों का निपटारा करें ताकि आमजन को लघु सचिवालय के बार-बार चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिकायतों से संबंधित रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट रखा जाए तथा शिकायतकर्ता को समय पर सूचना उपलब्ध करवाई जाए, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। इस दौरान एसीपी राजदीप मोर,तहसीलदार कीर्ति सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सोनीपत की टॉप-18 आंगनबाड़ी वर्कर्स सम्मानित : एडीसी अजय चोपड़ा

ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने और उनमें सीखने की रुचि विकसित करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स का समर्पण सराहनीय है।

वे सोमवार को स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली सोनीपत जिले की टॉप-18 आंगनबाड़ी वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा और जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण कुमारी ने रॉकेट लर्निंग टीम की उपस्थिति में सभी 18 आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत वर्कर्स प्रतिदिन बच्चों को विभिन्न शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान कर रही हैं। इससे बच्चों में सीखने की रुचि विकसित होने के साथ-साथ वे स्कूल शिक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स की मेहनत और निरंतर प्रयासों से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने सभी सम्मानित वर्कर्स को बधाई देते हुए कहा कि उनका कार्य अन्य आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए भी प्रेरणादायक है। उन्होंने सभी वर्कर्स से इसी उत्साह, लगन और समर्पण के साथ कार्य करते हुए बच्चों की शिक्षा एवं पोषण के स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण कुमारी सहित रॉकेट लर्निंग टीम से कार्यक्रम प्रबंधक रीतेश कुमारी, जिला समन्वयक कोमल और वंशिका उपस्थित रहे।

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी विभाग गंभीरता से करें काय : डीसी नेहा सिंह

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी नेहा सिंह

ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। सर्दियों में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं वर्ष 2027 के लिए दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तैयार किए जाने वाले वार्षिक एक्शन प्लान के संबंध में सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य सचिव तरुण कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)के माध्यम से एनसीआर के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की। बैठक में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए जाने वाले प्रमुख कार्यों और एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों से एक-एक कर उनके जिलों की तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वीसी के उपरांत उपायुक्त नेहा सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ



बैठक कर निर्देश दिए कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी विभाग नियमित रूप से मॉनिटरिंग एवं सर्विलेंस सुनिश्चित करें। कुंडली, बड़ी और खरखौदा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। अपशिष्ट और बायोमास जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों की टीमें दिन और रात लगातार फील्ड में निरीक्षण करें।

नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अधिक से अधिक चालान किए जाएं। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि जिला में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में लगातार अंतर-विभागीय बैठकें आयोजित कर अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

जिले में एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग किया जा रहा है तथा सड़कों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जा रही है। सोनीपत शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुंडली, बड़ी और खरखौदा सहित औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं।

हरियाणा में गली निर्माण, सरकारी धन और फसल बीमा से जुड़े घोटालों की निष्पक्ष जांच हो : कुमारी सैलजा

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में सामने आ रहे कथित भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

सांसद ने कहा कि प्रदेश में कहीं गली निर्माण में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं, कहीं सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं तो कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन सभी मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि पिछले लंबे समय से विपक्ष द्वारा प्रदेश में अनेक कथित घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया



विपक्ष लंबे समय से उजागर कर रहा अनेक कथित घोटाले, सरकार की गोलमाल नीतियों के कारण लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामले : कुमारी सैलजा

जाता रहा है, लेकिन सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार की गोलमाल नीतियों, प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही के अभाव ने व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार को केवल राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सांसद ने कहा कि सार्वजनिक धन जनता की मेहनत की कमाई है और उसकी एक-एक पाई का हिसाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। विकास कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल, फर्जी भुगतान, अधूरे कार्यों के बिल बनाने तथा योजनाओं के लाभार्थियों से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

केवल आरोप लगने से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन गंभीर शिकायतों को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बनाई गई है। यदि किसानों के खातों से प्रीमियम कटने, बीमा रिकॉर्ड में गड़बड़ी, फसल नुकसान के गलत आकलन अथवा मुआवजे के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती हैं तो उनका समयबद्ध समाधान होना चाहिए। किसानों को अपने अधिकारों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, यह स्वीकार्य नहीं है। सांसद ने मांग की कि प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों के खर्च, स्वीकृत विकास परियोजनाओं, जारी भुगतान और लंबित जांचों का पूरा विवरण सार्वजनिक करे। जिन मामलों में प्रथम दृष्टया वित्तीय गड़बड़ी के प्रमाण मिलें, उनकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए। जांच में दोष सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी जनता के हितों की रक्षा करना है।

मेला श्री कपाल मोचन आदि बद्री में आयुष विभाग की प्रदर्शनी में आयुर्वेदिक जीवन शैली का दिया जा रहा संदेश

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के जिला यमुनानगर के बिलासपुर में 20 से 24 नवम्बर तक आयोजित मेला श्री कपाल मोचन आदि बद्री में प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनी में आयुष विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है, जहां आने वाले श्रद्धालुओं को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एवं पंचकर्म चिकित्सा पद्धतियों आदि के बारे में जानकारी देकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान विशेष रूप से 'रसोई घर एक आदर्श औषधालय' की अवधारणा पर जोर देते हुए बताया जा रहा है कि हमारे घर में उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ सही मात्रा एवं



सही समय पर सेवन करने से शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक आहार, विहार एवं योग के समन्वय से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक आहार में दूध, दही, छाछ, मूंग व मसूर की दाल, दलिया, ओट्स, गेहूं, बाजरा, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, सीमित मात्रा में घी एवं सूखे मेवे और नारियल पानी जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना लाभकारी है। संतुलित आयुर्वेदिक आहार शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, पाचन शक्ति सुधारने, मानसिक शांति एवं सकारात्मक मनोदशा बनाए रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने तथा बालों और हड्डियों के स्वास्थ्य में सहायक होता है।

उन्होंने आम जनता को योग एवं प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी है। श्रद्धालुओं को प्रतिदिन 30 से 40 मिनट योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। इसके अतिरिक्त, मेले में प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में जनगणना 2027 को लेकर विशेष स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल के माध्यम से श्रद्धालुओं एवं आमजन को आगामी जनगणना प्रक्रिया, स्व-गणना, जनगणना के महत्व तथा इसमें पूछे जाने वाले सवालों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े सरकार को विकास योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के उचित वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं। श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि स्व-गणना के माध्यम से नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं तथा जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं।

प्रदेश में मछली संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम को दिया जा रहा है बढ़ावा : श्याम सिंह राणा

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशु पालन एवं डेयरी तथा मत्स्य मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि अब प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक जिले की जलभराव वाली भूमि और उपयुक्त जल निकायों में 2-2 लाख मछली बीज का संचयन करेगी। राणा ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत हाल ही में यमुनानगर जिला के गांव बुद्ध माजरा के जल सागर से की गई है, जबकि पिछले वर्ष गांव बल्लेवाला में 2 लाख मछली बीज का संचयन किया गया था। उन्होंने बताया कि 'मछली-बीज के संचयन' की इस पहल से न केवल मछली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि जलीय जैव विविधता का संरक्षण भी होगा और स्थानीय मछुआरों व उद्यमियों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे।



उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य जल संसाधनों का बेहतर सदुपयोग करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना और मत्स्य पालकों की आय बढ़ाना है।

अब तक 49,034 एकड़ जल-क्षेत्र को मछली पालन के अधीन लाकर 1.47 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया जा चुका है। साथ ही, खारे पानी से प्रभावित 4,953 एकड़ जलक्षेत्र को सफेद झींगा पालन के अंतर्गत लाया गया है। राणा ने यह भी बताया कि अब तक लगभग 4,300 टन क्षमता की कोल्ड चेन और 18 मछली-फीड मिल स्थापित की जा चुकी हैं। इस वर्ष राज्य में तीन मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन भेजी गई हैं, जो किसानों को उनके तालाब पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार द्वारा करनाल और सिरसा में दो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी तथा हिसार और फरीदाबाद में दो मछली मंडियों का निर्माण किया जाएगा। भिवानी और सिरसा जिलों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। श्याम सिंह राणा ने बताया कि मत्स्य विभाग का योजना बजट वर्ष 2014-15 के लगभग 6.99 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में लगभग 242.40 करोड़ रुपये किया गया है जो कि प्रदेश सरकार की किसान हितैषी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इग्नू की दिसंबर परीक्षाएं 25 नवंबर से, हरियाणा में 1.69 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2026 टर्म-एंड परीक्षाएं 25 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 14 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में हरियाणा से कुल 1,69,046 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश भर में कुल 30 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 11 परीक्षा केंद्र विभिन्न जेलों में बनाए गए हैं। इन जेल परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,492 बंदी परीक्षार्थी भी परीक्षा देंगे। यह जानकारी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल के क्षेत्रीय निदेशक एवं प्रमुख डॉ. धर्म पाल ने दी। उन्होंने बताया कि भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, पानीपत एवं रोहतक जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला करनाल में तीन परीक्षा केंद्र जिला जेल करनाल, बुद्धा कॉलेज तथा विनायक पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि परीक्षाएं प्रतिदिन दो सत्रों में आयोजित होंगी। प्रथम सत्र प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा द्वितीय सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। डॉ. धर्म पाल ने आगे बताया कि परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों एवं व्यवस्थाओं से परीक्षा केंद्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत करवाने के लिए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के परीक्षा नियंत्रकों के लिए एक विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित प्राप्ति एवं वितरण, उत्तर पुस्तिकाओं के रखरखाव, परीक्षा संबंधित रिकॉर्ड के संधारण तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

अस्पताल में सिविल सर्जन के कार्यालय के भवन निर्माण को भी मिली मंजूरी

रेवाड़ी में बनेगा 300 बिस्तर का नागरिक अस्पताल : स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचा को दिन प्रतिदिन मजबूत किया जा रहा है , इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिविल अस्पताल रेवाड़ी के परिसर में 300 बिस्तर का नागरिक अस्पताल बनाने की स्वीकृति दे दी है, इसके भवन के निर्माण पर लगभग 34828.77 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रेवाड़ी और आसपास के जिलों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए वर्तमान सिविल अस्पताल के बुनियादी ढांचे को एक आधुनिक, व्यापक और उच्च-क्षमता वाले



अस्पताल परिसर में अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से प्रस्तावित 300 बिस्तरों वाले इस नए अस्पताल ब्लॉक को 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर तथा ऊपर 6 मंजिल भवन फ्रेम्ड आरसीसी संरचना के रूप में तैयार किया जाएगा।

यह नया भवन भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप होगा, जिसमें अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक, क्लिनिकल, क्रिटिकल केयर और सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने आगे बताया कि सीएम ने भिवानी जिला के बवानी खेड़ा में 50 बिस्तरीय सिविल हॉस्पिटल बनाने की स्वीकृति दे दी है जिस पर 5519.04 लाख रुपए की लागत आएगी। क्योंकि बवानी खेड़ा में पहले से चले आ रहे अस्पताल के भवन की हालत खस्ता हो गई थी, ऐसे में वर्तमान जरूरतों को देखते हुए अधिक बिस्तर वाले आधुनिक अस्पताल के लिए सीएम ने घोषणा की थी, अब उस घोषणा को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। आरती सिंह राव ने आगे जानकारी दी कि कुरुक्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सिविल सर्जन के कार्यालय के निर्माण हेतु भी मुख्यमंत्री ने 2630.57 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है।

एशिया के सबसे प्रभावी नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नंबर पर, लोवी इंस्टिट्यूट ने जारी की लिस्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)



विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्रीय नेतृत्व के आकलन में भी सुधार किया है। उन्हें तीन पायदान का उछाल मिला है और जिनपिंग के बाद एशिया का दूसरा सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता माना गया है। इन नतीजों पर टिप्पणी करते हुए, लोवी इंस्टीट्यूट में दक्षिण-पूर्व एशिया कार्यक्रम के निदेशक और 'एशिया पावर इंडेक्स' के प्रोजेक्ट लीड, डॉ. हंटर मार्स्टन ने 'एक्स' पोस्ट में लिखाः भारत का प्रभाव बढ़ा है। भारत 40.5 के स्कोर पर पहुंच गया है, जिससे एक बड़ी शक्ति के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत हुई है

भारत ने पूरी धमक के साथ एशिया में अपना इकबाल बुलंद किया है। हम इस महाद्वीप के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में पहचाने गए हैं। वहीं हमारे देश की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित थिंक टैंक लोवी इंस्टिट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स फेहरिस्त में खास जगह दी है। उन्हें इस क्षेत्र का दूसरा सबसे प्रभावी नेता बताया गया है।

पीएम मोदी से ऊपर यानी शीर्ष पायदान पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रखा गया है। रिपोर्ट में भारत के कूटनीतिक प्रभाव को उसकी प्रमुख ताकत बताया गया है। इस श्रेणी में भारत को 70.3 अंक मिले हैं। विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्रीय नेतृत्व के आकलन में भी सुधार किया है। उन्हें तीन पायदान का उछाल मिला है और जिनपिंग के बाद एशिया का दूसरा सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता माना गया है। इन नतीजों पर टिप्पणी करते हुए, लोवी इंस्टीट्यूट में दक्षिण-पूर्व एशिया कार्यक्रम के निदेशक और 'एशिया पावर इंडेक्स' के प्रोजेक्ट लीड, डॉ. हंटर मार्स्टन ने 'एक्स' पोस्ट में लिखाः भारत का प्रभाव बढ़ा है। भारत 40.5 के स्कोर पर पहुंच गया है, जिससे एक बड़ी शक्ति के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत हुई है। 2018 के बाद से चीन के साथ भारत का अंतर अब सबसे कम है। आर्थिक क्षमता में कुछ गिरावट के बावजूद, शी जिनपिंग के बाद पीएम मोदी को अब दूसरा सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता माना गया है।

रिपोर्ट में भारत को प्रमुख शक्ति (मेजर पावर) का दर्जा दिया गया है। 2026 एशिया पावर इंडेक्स में 27 देशों और क्षेत्रों का मूल्यांकन 131 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इसमें शक्ति से जुड़े आठ पैमानों को शामिल किया गया जिनमें आर्थिक और सैन्य क्षमता, मजबूती, राजनयिक प्रभाव और आर्थिक संबंध शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और चीन क्रमशः शीर्ष दो स्थानों पर बने हुए हैं। वहीं, भारत ने अपने राजनयिक प्रभाव, रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक पहुंच और भविष्य के संसाधनों में सुधार करके क्षेत्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत को इस सूचकांक में 100 में से 40.5 अंक मिले हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 0.5 अंक अधिक हैं। जापान 38.6 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि रूस 32.2 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। अमेरिका 78.9 अंकों के साथ पहले और चीन 73.6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है।

लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और चीन के बीच समग्र शक्ति का अंतर 2018 में इस सूचकांक की शुरुआत के बाद सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। भारत की सबसे मजबूत स्थिति भविष्य के संसाधनों (फ्यूचर रिसोर्सेज) के क्षेत्र में रही, जहां उसे तीसरा स्थान मिला है। इस श्रेणी में भारत को 56.2 अंक प्राप्त हुए। आर्थिक क्षमता में भी भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है। रिपोर्ट में भारत की आर्थिक स्थिति को मिला-जुला बताया गया है। आर्थिक क्षमता का स्कोर थोड़ा घटकर 26.4 अंक रह गया। इसके अलावा, देश से बाहर होने वाले निवेश में करीब 20 अरब डॉलर की गिरावट का भी उल्लेख किया गया है।

हालांकि, भविष्य के संसाधनों के मामले में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा। आर्थिक विकास के अनुमान में सुधार के चलते इस श्रेणी में उसका स्कोर बढ़कर 56.2 अंक हो गया। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत ने क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की दिशा में प्रगति की है। आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर चुनौतियों के बावजूद रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय संबंधों और भविष्य की संभावनाओं ने एशिया में भारत की स्थिति को मजबूती दी है।

धन की वृद्धि के लिए मोदी ने बताए 8 सूत्र, महाभारत के श्लोक से दिया समृद्धि का मंत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया है। संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से पीएम मोदी ने लोगों को 8 गुणों के माध्यम से धन की निरंतर वृद्धि और समृद्धि का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री की ओर से एक्स पोस्ट में संस्कृत श्लोक, 'धृतिर्दाक्ष्यं संयमो बुद्धिरग्र्या धैर्य शौर्य देशकालोऽप्रमादः। स्वल्पस्य वा महतो वापि वृद्धौ धनस्यैतान्यष्ट समिन्धनानि।।' साझा किया गया है, जिसका हिंदी भावार्थ है कि धृति, कुशलता, आत्मसंयम, श्रेष्ठ बुद्धि, धैर्य, शौर्य, देश और काल का उचित ज्ञान तथा सावधानी, ये आठ धन की निरंतर वृद्धि और समृद्धि के आधार हैं।

पीएम की ओर से साझा किया गया यह श्लोक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है, जिसे बाद में सुभाषित-संग्रहों में भी स्थान मिला है। इसके माध्यम से धन और समृद्धि की वृद्धि के आठ आवश्यक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि चाहे पूंजी छोटी (स्वल्प) हो या बड़ी (महत), उसे बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए केवल भाग्य नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर आठ व्यावहारिक और चारित्रिक गुणों का होना अनिवार्य है। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए 'समिधा' (लकड़ी) की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धन की वृद्धि के लिए ये आठ गुण 'समिन्धन' (ईंधन) का कार्य करते हैं। यानी दृढ़ता, कार्यकुशलता, संयम, श्रेष्ठ बुद्धि, धैर्य, पराक्रम, देश-काल (परिस्थिति और समय) की समझ तथा सावधानी (प्रमाद न करना) छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के धन की वृद्धि करने के लिए ये आठ गुण मुख्य साधन (ईंधन) हैं। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि किसी भी लक्ष्य या आर्थिक योजना पर निरंतर टिके रहने की मानसिक शक्ति होनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों से नहीं भटकना चाहिए।

45वां व्यापार मेला : मेले में पहुंचे 1.20 लाख से ज्यादा लोग, खरीदारी-व्यंजनों का उठाया लुत्फ



नई दिल्ली (एजेंसी)

45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में रविवार को दर्शकों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। वीकेंड के दूसरे दिन शनिवार के मुकाबले 71 फीसदी अधिक लोग मेले में पहुंचे। सुबह से ही दर्शकों की आवाजाही शुरू हुई जो कि देर शाम तक करीब 1.20 लाख तक पहुंच गई। छुट्टी के दिन परिवारों और दोस्तों के साथ पहुंचे लोगों ने देशभर के उत्पादों, हस्तशिल्प, खानपान और मनोरंजन गतिविधियों का आनंद लिया। इससे स्टॉल संचालकों और कारोबारियों में भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद जगी है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के अनुसार, रविवार को दिल्ली-एनसीआर के अलावा दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे। किसी ने राज्यों के मंडपों में देशभर के उत्पादों और हस्तशिल्प की जानकारी ली तो किसी ने खरीदारी की।

खानपान क्षेत्र में अलग-अलग राज्यों के व्यंजनों का स्वाद लेने वालों की भी भीड़ रही। बच्चों और युवाओं के बीच मनोरंजन गतिविधियां आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। छुट्टी का दिन होने से सुबह से ही दर्शक आने लगे। दिन चढ़ने के साथ मेले में लोगों की संख्या बढ़ती गई। विभिन्न मंडपों में प्रदर्शित उत्पादों को देखने, उनकी कीमत पूछने और खरीदारी करने वालों की आवाजाही रही। परिवारों ने एक ही परिसर में देश के अलग-अलग राज्यों की संस्कृति, खानपान और उत्पादों को देखने का आनंद लिया। इस बार मेले में खरीदारी के साथ मनोरंजन और नए अनुभवों के विकल्प भी दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। बच्चे और युवा खेल तथा अनुभव आधारित गतिविधियों में रुचि दिखा रहे हैं। वहीं खानपान क्षेत्र में लोगों को अलग-अलग राज्यों के व्यंजनों का स्वाद मिल रहा है। आईटीपीओ की जानकारी के अनुसार, मेले में 90 से अधिक खानपान केंद्र लगाए गए हैं। वीकेंड पर उमड़ी भीड़ से स्टॉल संचालकों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। खासकर हस्तशिल्प, घरेलू उपयोग के सामान, कपड़े, सजावटी उत्पाद और खानपान से जुड़े स्टॉल पर दर्शकों की आवाजाही कारोबारियों के लिए अहम रही। छुट्टी के दिन परिवारों के साथ पहुंचे लोगों ने उत्पादों की जानकारी लेने के साथ खरीदारी में भी दिलचस्पी दिखाई।

दिल्ली : बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, टिन शेड के नीचे पढ़ रहे 1000 बच्चे

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक नगर स्थित दिल्ली सरकार के एक स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1,000 छात्रों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने दिल्ली सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। यह आदेश सोशल ज्यूरिस्ट (एक सिविल राइट्स ग्रुप) की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि अशोक नगर स्थित दिल्ली सरकार का यह स्कूल पूरी तरह टिन शेड से बना है, जहां करीब 1,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में की गई मांगों की प्रकृति को देखते हुए प्रतिवादियों (दिल्ली सरकार) से यह जानना जरूरी है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता समीर वशिष्ठ ने अदालत को आश्वासन दिया कि यदि स्कूल की संरचना में हर तरह का सुधार किया जा रहा है। अदालत ने दिल्ली सरकार को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

'विदेशों में भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है', रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तंज

नई दिल्ली (एजेंसी)



भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेशी दौरे के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का ठेका लिया है। नई दिल्ली में बातचीत में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने लोवी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं और देश के बारे में भारी अज्ञानता दिखा रहे हैं। वे भारत को सबसे खराब रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, आज मैं सभी का ध्यान ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक 'लोवी इंस्टीट्यूट' की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताजा रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया स्थित 'लोवी इंस्टीट्यूट' एक स्वतंत्र संस्था है, जिसकी स्थापना 2003 में फ्रैंक लोवी ने की थी। यह संस्था वैश्विक रणनीतिक और आर्थिक रुझानों का अध्ययन करती है। इसकी हालिया रिपोर्ट 'एशिया पावर इंडेक्स 2026' है। इस संस्थान ने 131 संकेतकों के आधार पर एशिया के 27 देशों का अध्ययन किया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में भारत को 40.5 अंक मिले हैं, जो 2018 के मूल्यांकन में मिले अंकों की तुलना में एक सुधार है।

इसकी कुछ मुख्य बातें साझा करना चाहूंगा। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। भाजपा नेता ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव में हुई वृद्धि को दर्शाता है, जो उसकी आर्थिक क्षमता और स्थिरता का परिणाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने 'भविष्य के संसाधनों' के क्षेत्र में सुधार किया है। इसमें उन निवेशों और अवसरों को देखा जाता है, जो भारत के भविष्य को आकार दे सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस श्रेणी में भारत के अंक बढ़कर 56.2 हो गए हैं, जो उसकी आर्थिक क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कूटनीतिक प्रभाव के बारे में बताया है और व्यापक परिदृश्य पर भी चर्चा की है। अब बात करते हैं आर्थिक संबंधों में स्थिरता की। भारत उन पांच देशों में शामिल है, जिनके आर्थिक संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई है। भारत इकलौता ऐसा देश है, जिसके आर्थिक संबंधों में गिरावट नहीं आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने रक्षा नेटवर्क में 18.6 अंक हासिल किए हैं और दो स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर आ गया है। भारत में आर्थिक विकास की एक नई लहर आई है।

पहाड़ों की बर्फबारी से बढ़ेगी दिल्ली-एनसीआर में ठिठुरन, वायु गुणवत्ता के 'रेड जोन' में लौटने की आशंका

नई दिल्ली (एजेंसी)



पहाड़ों पर बदलते मौसम का असर अब मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और भी जोर पकड़ेगी। इस हफ्ते न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की प्रबल संभावना है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले छह दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के आसमान में कोहरे का डेरा रहने वाला है। 23 नवंबर को दिन की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ होगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 24 नवंबर को तापमान में मामूली गिरावट दर्ज होगी। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर आ जाएगा, जबकि अधिकतम 25 डिग्री रहेगा। मौसम हल्का कोहरा बना रहेगा। 25 नवंबर को ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री रहेगा।

कोहरे की तीव्रता बढ़कर मध्यम कोहरा तक पहुंच जाएगी। 26 नवंबर को सबसे अधिक ठंड इस दिन महसूस की जा सकती है। न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आसमान में मध्यम कोहरा छाया रहेगा। 27 और 28 नवंबर को तापमान में स्थिरता रहेगी। न्यूनतम पारा 10 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दोनों ही दिन मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम में आ रहे इस बदलाव का सीधा असर एनसीआर की हवा पर पड़ेगा। ठंड के जोर पकड़ते ही और हवा की रफ्तार धीमी होने के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में जमा होने लगेंगे।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, जैसे ही तापमान में तेजी से गिरावट आएगी, एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) फिर से 'रेड जोन' यानी 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाएगा। फिलहाल, मौसम में आंशिक सुधार देखने को मिल रहा है और हवा कुछ हद तक साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ने की पूरी आशंका है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'खराब': 249 दर्ज हुआ एक्यूआई

सोमवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी रही। सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजधानी का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 249 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार, नोएडा में एक्यूआई 214 रहा, बुलंदशहर में 185, गाजियाबाद में 237, हापुड़ में 219 रहा। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाबी बाग के बाद बवाना में 273 और चांदनी चौक में 271 एक्यूआई दर्ज हुआ। ये सभी 'खराब' श्रेणी में थे। आनंद विहार (237), अशोक विहार (240), नरेला (239), ओखला फेज 2 (213), रोहिणी (252), सोनिया विहार (215), पटपड़गंज (208), मंदिर मार्ग (225), मेजर ध्यान चंद स्टेडियम (202), अलीपुर (246), आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 (217) और आरके पुरम (252) में भी वायु गुणवत्ता 'खराब' रही।

कोर्ट ने मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला आठ साल पुराने आपराधिक मानहानि केस से जुड़ा है, जिसे विकास सांकृत्यायन (उर्फ विकास पांडे) ने 'भाजपा आईटी सेल पार्ट 2' शीर्षक वाले एक वीडियो को लेकर दायर किया था। साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी के अदालत में पेश न होने पर वारंट जारी किया है। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि कार्यवाही के दौरान उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने में बार-बार मुश्किलें आ रही थीं। अब अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है।

यह नया आदेश तब आया है, जब अदालत ने 31 अक्टूबर को ध्रुव राठी के खिलाफ एक और जमानती वारंट जारी किया था और निर्देश दिया था कि इसे उनके गुरुग्राम वाले पते पर तामील कराया जाए। हालांकि, इस वारंट की तामील नहीं हो सकी। इससे पहले, 17 अक्टूबर को भी अदालत ने इस यूट्यूबर के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया था। ऐसा तब किया गया, जब अदालत को बताया गया कि नया समन तामील नहीं हो सका क्योंकि उनके घर पर ताला लगा हुआ था। 17 अक्टूबर वाले वारंट की भी तामील नहीं हो पाई क्योंकि अदालत को जानकारी मिली कि यह वारंट ऑस्ट्रिया के एक गलत पते पर भेज दिया गया था। यह मामला 'भाजपा आईटी सेल पार्ट 2' नाम के एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर विकास पांडे की छवि खराब की गई थी। 2018 में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया था।

बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि इसे साझा करके उनसे गलती हुई थी। सोशल मीडिया पेज 'आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी' के संस्थापक पांडे ने आरोप लगाया था कि इस वीडियो और इसके रीट्वीट किए जाने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। ध्रुव राठी के खिलाफ कार्यवाही 2019 से ही लंबित थी क्योंकि उन्हें समन तामील कराने में बार-बार मुश्किलें आ रही थीं। शिकायतकर्ता का कहना था कि राठी के लगातार भारत से बाहर रहने के कारण मामले में देरी हुई। राठी ऑस्ट्रिया में रहते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था क्योंकि केजरीवाल ने एक रीट्वीट से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले को चुनौती दी थी।

फरवरी 2024 में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वीडियो को रीट्वीट करना उनसे हुई गलती थी। जस्टिस संजीव खन्ना (जो बाद में सीजेआई बने और अब रिटायर हो चुके हैं) और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

एसएंडपी ग्लोबल ने भारत की विकास दर को 7% पर बरकरार रखा, महंगाई को बताया जोखिम

नई दिल्ली (एजेंसी)



एसएंडपी ग्लोबल ने सोमवार को कहा कि भारत की विकास दर वित्त वर्ष 27 और वित्त वर्ष 28 में 7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इसे मजबूत निर्यात, सार्वजनिक निवेश और बढ़ते उपभोग का फायदा मिलेगा। हालांकि, महंगाई और मौसम संबंधी कारक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जोखिम बने हुए हैं। एसएंडपी ग्लोबल ने अपनी 'इकोनॉमिक आउटलुट एशिया-पैसिफिक क्यू1 2027' रिपोर्ट में कहा कि जून और सितंबर तिमाहियों के दौरान भारत की विकास दर को मजबूत वस्तु निर्यात, सरकार के नेतृत्व वाले निवेश खर्च और घरेलू मांग से समर्थन मिला, जिसमें क्रेडिट ग्रोथ का भी अहम योगदान रहा। इसमें कहा गया, हमें उम्मीद है कि मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष और उसके अगले वित्त वर्ष, दोनों में भारत की जीडीपी विकास दर 7 प्रतिशत रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने बताया कि जून और सितंबर की तिमाहियों में विकास को वस्तुओं के मजबूत निर्यात, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश और घरेलू खपत से बढ़ावा मिला। घरेलू खपत में तेजी का एक बड़ा कारण क्रेडिट (उधार) में हुई अच्छी वृद्धि रही।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत के निर्यात प्रदर्शन को न केवल वस्तुओं की ऊंची कीमतों से फायदा मिला है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भागीदारी से भी मदद मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के सामान और केमिकल जैसे क्षेत्रों ने विशेष रूप से मजबूती दिखाई है, क्योंकि भारत अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता ला रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के दायरे का विस्तार कर रहा है। एजेंसी का अनुमान है कि मार्च 2027 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर औसतन 5.3 प्रतिशत रहेगी, जिसमें इसके और बढ़ने का जोखिम भी बना हुआ है। इसके चलते एसएंडपी ग्लोबल को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर में पॉलिसी दरों में 25 आधार अंक की और बढ़ोतरी करेगा। साथ ही, कहा कि 2027 की शुरुआत में दरों में एक और बढ़ोतरी होने की संभावना भी बढ़ गई है। अगले वित्त वर्ष को लेकर एजेंसी ने कहा कि मार्च 2028 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में महंगाई दर कम होकर 4.7 प्रतिशत पर आ जाएगी।

गोधरा ट्रेन अग्निकांड : सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को मेडिकल आधार पर राहत दी

नई दिल्ली (एजेंसी)



यह दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और लगभग 18 वर्षों से जेल में बंद है। जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दोषी इरफान सिराज पडो की मेडिकल स्थिति को देखते हुए उसे यह राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक दोषी की सजा पर रोक लगा दी और उसे मेडिकल आधार पर जमानत दे दी। यह दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और लगभग 18 वर्षों से जेल में बंद है। जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दोषी इरफान सिराज पडो की मेडिकल स्थिति को देखते हुए उसे यह राहत दी।

सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने भी यह माना कि उसे हृदय संबंधी (कार्डियोवैस्कुलर) बीमारी है। दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सजा पर रोक लगाने और अपनी आपराधिक अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। यह अपील 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह मामला फरवरी 2002 की गोधरा ट्रेन अग्निकांड की घटना से जुड़ा है, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे।

मार्च 2011 में एक ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से 11 को मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी जबकि 63 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अक्टूबर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने सभी 31 दोषियों की सजा को बरकरार रखा लेकिन 11 दोषियों की मौत की सजा को बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोषियों ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील दायर की। वहीं, गुजरात सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के फैसले को चुनौती दी। इससे पहले, अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आठ दोषियों को जमानत दी थी जबकि चार अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन अन्य दोषियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने इन दोषियों की विशिष्ट भूमिकाएं तय की थीं, जिनमें पथराव करना और सोने के आभूषण लूटना शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उनकी रिहाई की याचिकाओं को खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि उनकी लंबित आपराधिक अपीलों के गुण-दोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सम्पादकीय

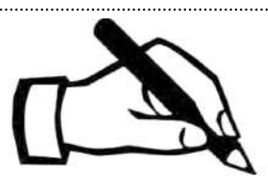

देश की एकता और विकास की जीवनरेखा

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में रेलवे केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण आधार है। देश के करोड़ों लोगों की दैनिक जिंदगी भारतीय रेल से जुड़ी हुई है। गांवों से शहरों तक, छोटे कस्बों से महानगरों तक और एक राज्य से दूसरे राज्य तक लोगों को जोड़ने में भारतीय रेलवे की भूमिका अतुलनीय है। भारतीय रेल ने दशकों से देश की विकास यात्रा को गति प्रदान की है और आज आधुनिक भारत के निर्माण में इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है।

भारतीय रेलवे का इतिहास देश की प्रगति और परिवर्तन की कहानी है। अंग्रेजों के शासनकाल में शुरू हुई रेल व्यवस्था आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक बन चुकी है। समय के साथ रेलवे ने अपनी सेवाओं, तकनीक और सुविधाओं में व्यापक बदलाव किए हैं। आज रेलवे केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दे रही है। रेलवे कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे देश के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलती है। जिन क्षेत्रों में पहले आवागमन कठिन था, वहां रेल सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत, आदिवासी बहुल क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में रेल नेटवर्क का विस्तार राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी अहम भूमिका निभाती है। मालगाड़ियों के माध्यम से कोयला, खाद्यान्न, सीमेंट, लौह अयस्क और अन्य औद्योगिक वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। इससे उद्योगों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से परिवहन लागत कम करने, बाजारों तक पहुंच आसान बनाने और आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलती है। रेलवे पर्यटन क्षेत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक शहरों और प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्रों तक रेल पहुंच बढ़ने से पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिलती है। हालांकि, भारतीय रेलवे के सामने अभी भी अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार, ट्रेनों की समयबद्धता, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता जैसे विषयों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे की व्यवस्थाओं पर दबाव डालती है। ऐसे समय में अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन, बेहतर टिकट व्यवस्था और यात्रियों को सही जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। रेलवे की प्रगति तभी सार्थक होगी, जब आधुनिक सुविधाओं के साथ आम यात्रियों की जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जाए।

गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए सुलभ किराया, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं तथा छोटे स्टेशनों पर आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता रेलवे विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। तकनीकी आधुनिकीकरण के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी रेलवे की कार्यप्रणाली में दिखाई देनी चाहिए।

गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व

संत राजिन्दर सिंह जी महाराज

भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक गुरु को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में पूर्ण गुरु को परमात्मा के समान माना गया है। आज दुनियाभर में हम सब गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। उन जैसे पूर्ण गुरु सृष्टि की शुरूआत से ही इस धरती पर हमारी आत्मा को पिता-परमेश्वर से मिलाने के लिए आते रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म सन् 1469 ई. को कार्तिक मास की पूर्णिमा को तलवंडी शहर (पाकिस्तान) में हुआ था।

गुरु नानक देव जी महाराज सिर्फ सिक्खों के लिए ही नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए थे जैसे संपूर्ण मनुष्य जाति उनके लिए थी। ऐसे महापुरुष इस धरती पर रोशनी की एक किरण बनकर आते हैं और अपने रूहानी नूर से 84 लाख जियाजून में फंसी हुई आत्माओं को पिता-परमेश्वर से एकमेक कर देते हैं। उनके मुख्य उपदेशों में 'किरत करो, नाम जपो और वंड छको' प्रमुख हैं। जिससे तात्पर्य है कि इंसान अपनी मेहनत की कमाई करता हुआ प्रभु का सिमरन करे और सबके साथ मिल-बाँटकर खाए।

गुरुबाणी में गुरु नानक देव जी महाराज इस संसार के बारे में फ़रमाते हैं, 'नानक दुखिया सब संसार' कि इस दुनिया में हरेक इंसान दुःखों से घिरा हुआ है। कोई न कोई दुःख सबको लगा हुआ है। हर इंसान सोचता है कि सबसे ज़्यादा दुःख मुझे है। अगर देखा जाए तो जब तकलीफ आती है तभी हम प्रभु को याद करते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर हम अपने कार्यों में मस्त हो जाते हैं। ये दुःख और सुख का चक्र हमारे जीवन में चलता रहता है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम हमेशा-हमेशा के सुख को कैसे पा सकते हैं? इस बारे में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर फ़रमाया करते थे कि 'सो सुखिया जो नाम आधार।' यानि जो व्यक्ति पिता-परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ गया वही सुखी है। नाम के साथ जुड़ने के लिए हमें किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाना होगा, जो हमें अपनी दयामेहर से प्रभु की ज्योति और श्रुति से जोड़ देते हैं, जिसे गुरुबाणी में 'नाम' कहा गया है और जिसका अनुभव हम अपने अंतर ध्यान-अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं।

ध्यान-अभ्यास के द्वारा हमें अपने आपको असली रूप में देखते हैं। यह वो रूप है जो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। वो आत्मा जो पिता-परमेश्वर का अंश है और उनके प्रेम से भरपूर है। वो आत्मा जो चेतन है, और जो हमें जान दे रही है। जब हमारी आत्मा पिता-परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करती है तो वो हर समय प्रभु-प्रेम की मस्ती की अवस्था में रहती है।

मस्ती की इस अवस्था को गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी में कहा है कि, 'नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात'। जो नाम की खुमारी है, जो प्रभु का अमृत हमारे अंदर बरस रहा है, जब ध्यान-अभ्यास के द्वारा हम अपने अंतर में उसका अनुभव करते हैं तो उसकी मस्ती और उसका आनंद दिन-रात चौबीस घंटे हमारे साथ रहता है और जब हमारी आत्मा यह अनुभव करती है तो उसका मिलाप पिता-परमेश्वर से हो जाता है।

गुरु नानक देव जी महाराज ने 'एक पिता एकस के हम बारिक' के संदेश को भी समस्त संसार में फैलाया। उनके इस उपदेश के अनुसार हम सब एक ही पिता-परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हम आपस में प्रेम-प्यार से रहें और एक-दूसरे की मदद करें। जब हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तो हम अपने भीतर प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं और ऐसे महापुरुष इसी प्रभु के प्रेम को हम सबको बांटने के लिए इस धरा पर आते हैं। जिससे कि हमें जिंदगी जीने की सही राह मिलती है। ऐसे पूर्ण गुरु हमें समझाते हैं कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य अपने आपको जानना और पिता-परमेश्वर को पाना को इसी जीवन में पूरा कर सकते हैं।

आईये! गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को हम सही मायनों में तभी मना सकते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें और उन पर अमल करें।

बिजली संकट की आहट

डॉ. सत्यवान सौरभ

बिजली किसी सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन भर नहीं, बल्कि उसकी विकास क्षमता की वास्तविक परीक्षा है। जब उद्योग उत्पादन रोकने को मजबूर हों, किसान सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार करें, शहरों में गर्मी के दौरान कटौती हो और उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़े, तब ऊर्जा आत्मनिर्भरता के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत का बिजली क्षेत्र आज इसी विरोधाभास से जूझ रहा है। एक ओर रिकॉर्ड बिजली उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और भविष्य की बड़ी योजनाओं का उत्सव है, दूसरी ओर ईंधन संकट, कमजोर वितरण कंपनियां, अपर्याप्त भंडारण और मांग के दबाव जैसी चुनौतियां मौजूद हैं।

बिजली क्षेत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारी ऊर्जा योजना कई बार वास्तविक मांग के बजाय स्थापित क्षमता के आंकड़ों पर अधिक केंद्रित दिखाई देती है। कितने मेगावाट संयंत्र स्थापित हुए, कितनी सौर परियोजनाएं शुरू हुईं और कितनी नई योजनाओं की घोषणा हुई–इन आंकड़ों से विकास का आकलन किया जाता है। लेकिन उपभोक्ता के लिए असली सवाल यह है कि जरूरत पड़ने पर बिजली उपलब्ध है या नहीं। स्थापित क्षमता और वास्तविक आपूर्ति के बीच का अंतर ही ऊर्जा नियोजन की गंभीर चुनौती है। बिजली संयंत्र का होना और उसका संकट के समय लगातार उत्पादन करना दो अलग-अलग बातें हैं। कोयले पर निर्भरता कम करने की बात वर्षों से हो रही है, लेकिन ताप विद्युत अभी भी भारतीय बिजली व्यवस्था की रीढ़ है। इस निर्भरता को स्वीकार करने के बजाय कई बार ऊर्जा संक्रमण की बहस को केवल स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार तक सीमित कर दिया जाता है।

कोयले की आपूर्ति, रेलवे परिवहन, संयंत्रों में पर्याप्त भंडार और उत्पादन इकाइयों के रखरखाव पर गंभीर ध्यान नहीं दिया गया तो संकट के समय सारी योजनाएं कागज पर ही रह जाएंगी। ऊर्जा नीति में विरोधाभास नहीं, व्यावहारिकता चाहिए। जब तक वैकल्पिक स्रोत पर्याप्त, स्थिर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं बनते, तब तक पारंपरिक उत्पादन व्यवस्था को कमजोर करना जोखिमपूर्ण होगा। सौर ऊर्जा का विस्तार निश्चित रूप से भविष्य की जरूरत है, लेकिन केवल सूरज चमकने के समय बिजली उपलब्ध होना ऊर्जा सुरक्षा नहीं है। शाम होते ही सौर उत्पादन घटता है, जबकि घरेलू और व्यावसायिक मांग कई क्षेत्रों में बढ़ जाती है। इस अंतर को भरने के लिए बैटरी



भंडारण, पंप्ड स्टोरेज, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और पर्याप्त नियंत्रित उत्पादन क्षमता की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या हमारी योजनाएं इन व्यवस्थाओं को उसी गंभीरता से विकसित कर रही हैं, जिस गंभीरता से सौर क्षमता के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं? यदि भंडारण और ग्रिड की तैयारी पीछे रह गई, तो नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार भी नई अस्थिरता पैदा कर सकता है। बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय बदहाली इस संकट का एक ऐसा पहलू है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

वर्षों से घाटे में चल रही वितरण कंपनियां, तकनीकी नुकसान, बिजली चोरी, कमजोर बिलिंग व्यवस्था और राजनीतिक दबाव के कारण आर्थिक रूप से कमजोर होती रही हैं। मुफ्त बिजली और सब्सिडी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यदि उसका भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से नहीं होता, तो अंततः नुकसान बिजली व्यवस्था को उठाना पड़ता है। उपभोक्ता को राहत देने के नाम पर वितरण कंपनियों को वित्तीय संकट में छोड़ देना दूरदर्शी नीति नहीं है। सरकारों को यह समझना होगा कि कमजोर डिस्कॉम के सहारे विश्वस्तरीय बिजली व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। पारेषण व्यवस्था भी बिजली क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कमजोरी है।

बिजली उत्पादन बढ़ा देना पर्याप्त नहीं, यदि उसे जरूरत वाले क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क मजबूत न हो। कई बार बिजली की उपलब्धता और बिजली की जरूरत अलग-अलग क्षेत्रों में होती है, लेकिन सीमित पारेषण क्षमता के कारण उसका प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता। आधुनिक ट्रांसमिशन लाइनें, अंतरराज्यीय नेटवर्क, स्मार्ट ग्रिड और तकनीकी निगरानी पर निवेश अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। बिजली व्यवस्था में एक कमजोर कड़ी पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकती है। बढ़ती बिजली मांग को भी अब सामान्य वृद्धि मानकर नहीं चलाया जा सकता। औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, शहरीकरण और बढ़ती गर्मी ने बिजली की जरूरतों का स्वरूप बदल दिया है। आने वाले वर्षों में केवल पुराने मांग अनुमान पर्याप्त नहीं होंगे। सरकार, बिजली कंपनियों और नियामकों को भविष्य की जरूरतों का वास्तविक आकलन करना होगा। अन्यथा हर गर्मी, हर औद्योगिक विस्तार और हर मांग वृद्धि के साथ संकट प्रबंधन की स्थिति पैदा होती रहेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का अर्थ केवल नई परियोजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करना भी है। बिजली खरीद में पारदर्शिता, वितरण कंपनियों के घाटे का वास्तविक आकलन, समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन, स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा दक्षता और मांग प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उद्योगों को ऊर्जा बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाए और घरेलू उपभोक्ताओं को भी दक्ष उपकरणों तथा बेहतर उपयोग के प्रति जागरूक बनाया जाए। बिजली की बचत केवल नैतिक अपील से नहीं, बल्कि तकनीक, प्रोत्साहन और प्रभावी नीति से संभव होगी।

भारत को ऊर्जा संक्रमण के नाम पर अव्यावहारिक लक्ष्य और बिजली संकट के नाम पर पुराने ढांचे से चिपके रहने–दोनों अतियों से बचना होगा। एक ओर पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, दूसरी ओर आर्थिक विकास और करोड़ों उपभोक्ताओं की जरूरतें। इन दोनों के बीच संतुलन ही वास्तविक ऊर्जा नीति है। स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार हो, लेकिन उसके साथ भंडारण, ग्रिड, भरोसेमंद उत्पादन और आर्थिक स्थिरता भी विकसित हो।

बिजली क्षेत्र की सफलता का पैमाना मेगावाट की घोषणाएं नहीं, बल्कि निर्बाध आपूर्ति, उचित बिल, मजबूत वितरण व्यवस्था और संकट के समय उपलब्ध ऊर्जा होना चाहिए। भारत को ऐसी बिजली व्यवस्था चाहिए जो केवल आंकड़ों में विशाल न हो, बल्कि नागरिकों के जीवन में भरोसेमंद हो। आखिर विकास का उजाला तभी सार्थक है, जब वह घोषणा-पत्रों और आंकड़ों से निकलकर घरों, खेतों, अस्पतालों और उद्योगों तक बिना बाधा पहुंचे। यही भारत की ऊर्जा नीति की असली कसौटी है।

तो इन्हें है देश के सम्मान की चिंता?

तनवीर जाफ़री

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। दरअसल पिछले दिनों न्यूयॉर्क स्थित अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत 'आर्थिक संकट' के मुहाने पर खड़ा है और यहाँ बेरोज़गारी, शिक्षा व्यवस्था तथा चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर समस्याएं हैं। भाजपा राहुल गाँधी द्वारा विदेश जाकर की जाने वाली ऐसी आलोचनाओं को सहन नहीं कर पाती और इसे देश विरोधी प्रचार बताती है। राहुल गांधी के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने इसे देश को बदनाम करने वाला बताया और उनके इस इस दावे को भी ख़ारिज किया कि भारत की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है या आर्थिक संकट में है।

रिजिजू ने यह आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी ने भारत की सभ्यता, परंपराओं, लोकतंत्र और संविधान को कमज़ोर करने वाली मानसिकता बना ली है। उन्होंने यह संगीन आरोप भी लगाया कि देश-विरोधी और वामपंथी विचारधारा वाली ताक़तें उन्हें प्रभावित कर रही हैं या उकसा रही हैं। रिजिजू ने राहुल को सुझाव दिए कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मृत' या ख़त्म बताने वाले झूठे दावे करना बंद करें। भाजपा के अन्य कई नेता पहले भी राहुल गांधी की विदेश में की जानी वाली इसतरह की टिप्पणी पर अपनी ऐसी ही तीखी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट की बात केवल राहुल गांधी ही कहते हैं या देश के अन्य कई प्रमुख अर्थशास्त्री भी ऐसे ही विचार रखते हैं ? सच तो यह है कि पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर देश और दुनिया के कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों, पूर्व नीति-निर्माताओं और राजनेताओं ने समय-समय पर गंभीर चेतावनियां दी हैं। वे भी देश में अर्थव्यवस्था को लेकर संरचनात्मक संकट, बेरोज़गारी और धीमे निजी निवेश जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं।

उदाहरणार्थ पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भारत के जीडीपी आंकड़ों की गणना पद्धति, निजी निवेश में सुस्ती, रोज़गार सृजन की कमी और जीएसटी के बाद अनौपचारिक क्षेत्र को हुए नुक़सान पर लगातार गंभीर चिंता जताते रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने मध्यम वर्ग की स्थिर या घटती वास्तविक आय और महंगाई के कारण बढ़ रहे आर्थिक दबाव को लेकर चेतावनी दी है।

इसी तरह पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ऊर्जा आयात पर निर्भरता, रुपये की गिरावट और विदेशी पूंजी के बाहर जाने जैसे मुद्दों को उठाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता पर चिंता व्यक्त की है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और कौशिक बसु जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी अलग-अलग समय पर नोटबंदी के असर, जीडीपी की गणना में संभावित विसंगतियों, घटते निर्यात और रोज़गार संकट को लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। इसके अतिरिक्त भाजपा नेता व अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी भी अपनी ही पार्टी की सरकार की कई आर्थिक नीतियों–विशेषकर जीएसटी, नोटबंदी और बैंकिंग नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर संकट की चेतावनी देते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री व अर्थशास्त्री स्व डॉ. मनमोहन सिंह व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम बेरोज़गारी, महंगाई और मध्यम वर्ग की थमी हुई आय को देश की तीन सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियां बता चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने तो नोटबंदी और जीएसटी के क्रियान्वयन को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका बताया था।

इतना ही नहीं बल्कि विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशकों ने जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच भारतीय शेयर बाज़ार से लगभग 2.95 लाख करोड़ अर्थात क़रीब 35 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निवेश वापस निकाला है। हालांकि नवंबर 2026 में इन विदेशी निवेशकों द्वारा पुनः क़रीब 10.6 अरब की रिकॉर्ड वापसी भी की गयी है। फ़रवरी 2026 में ईरान पर हुए हमले और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक निवेशकों ने जोख़िम भरे बाज़ारों से पैसा निकालना शुरू किया। इसी लिए अकेले मार्च महीने में ही रिकॉर्ड 13 अरब डॉलर की निकासी हुई। वैश्विक अस्थिरता के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़े, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ने और महंगाई की आशंका पैदा हुई। 10-साल के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर 5.2% से अधिक का सुरक्षित रिटर्न मिलने के कारण निवेशकों ने भारतीय बाज़ार के मुक़ाबले अमेरिका में पैसा लगाना अधिक फ़ायदेमंद समझा। परन्तु सरकार का दावा है कि भारत 7% या उससे अधिक की दर से बढ़ने वाली दुनिया की सबसे तेज़ प्रमुख अर्थव्यवस्था है और पिछले 12-13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग ग़रीबी से बाहर आए हैं। दूसरी यही सरकार यह कहकर भी अपनी पीठ स्वयं थपथपाती रहती है कि वह देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन उपलब्ध करा रही है।

अब रहा सवाल विदेश की धरती पर भारत की बदनामी कराने का तो इस बदनामी का मापदंड आख़िर कौन तय करेगा ? याद कीजिये मई 2015 में चीन के शंघाई और दक्षिण कोरिया के सियोल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह टिप्पणी जिसमें उन्होंने कहा था कि 'एक दौर ऐसा था जब लोग सोचते थे कि उन्होंने पिछले जन्म में कौन-सा पाप किया था जो भारत में पैदा हुए,यह कैसा देश है और कैसी सरकार है, और लोग बाहर चले जाना चाहते थे।' प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर भारत में तीखी राजनीतिक बहस हुई थी। उस समय कई विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि विदेश में जाकर यह कहना कि भारत में जन्म लेना किसी पिछले पाप या अभिशाप जैसा माना जाता था, राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुँचाने वाला है।

इसी तरह भाजपा और उसके समर्थक जवाहरलाल नेहरू की कई नीतियों और निर्णयों का मूल्यांकन करते हुए उनकी आलोचना करते हैं। जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेहरू ने आधुनिक भारत, लोकतांत्रिक संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी, और उनके योगदान को नज़रअंदाज़ कर उन पर लगातार हमले किए जाते हैं।

विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के ही ऐसे और भी कई बयानों व गतिविधियों को देश की बदनामी करने वाली बताता है। जैसे कि अप्रैल 2015 में कनाडा के टोरंटो में प्रवासी भारतीयों की सभा में मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा था– 'जिनको गंदगी करनी थी, गंदगी करके चले गए, हम सफ़ाई करके जाएंगे' और 'हमारा मिशन 'स्किल इंडिया' है, न कि 'स्कैम इंडिया'।' उस समय कांग्रेस नेताओं ने इसे विदेशी धरती पर देश की पिछली उपलब्धियों और लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान क़रार दिया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भरोसे शासन? गलती मशीन की, भुगतेगा नागरिक!

डॉ. प्रियंका सौरभ

सरकारें आज तकनीक के सहारे तेज, पारदर्शी और प्रभावी शासन का दावा कर रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रशासनिक सुधार, जनसेवा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का नया औजार बताया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर देने से लेकर योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान, शिकायतों के विश्लेषण और निर्णय प्रक्रिया तक एआई का प्रवेश तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन तकनीक के चमकदार प्रचार के बीच एक बुनियादी सवाल दबता जा रहा है–यदि मशीन गलत निर्णय देगी, तो नागरिक न्याय के लिए किस दरवाजे पर दस्तक देगा? शासन में एआई का प्रयोग सुविधा का विषय जरूर है, लेकिन इसे जवाबदेही से मुक्त प्रयोगशाला नहीं बनाया जा सकता।

जनरेटिव एआई की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति यह है कि वह गलत जानकारी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकता है। वह ऐसे नियम, तथ्य, आँकड़े या पात्रता शर्तें बता सकता है, जो वास्तविकता में मौजूद ही न हों। आम नागरिक मशीन के उत्तर को सरकारी प्रमाणिकता समझ सकता है। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन की पात्रता गलत बता दी जाए, किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के संबंध में भ्रमित कर दिया जाए या किसी किसान को सरकारी योजना की गलत जानकारी मिल जाए, तो नुकसान केवल तकनीकी त्रुटि नहीं रह जाता; वह नागरिक के अधिकार पर चोट बन जाता है। सरकार के लिए एआई की गलती एक आँकड़ा हो सकती है, लेकिन नागरिक के लिए वह भूख, आर्थिक संकट, अवसर की हानि और निराशा बन सकती है।

विडंबना यह है कि सरकारी व्यवस्था में पहले से मौजूद मानवीय लापरवाही, अस्पष्ट नियम और लालफीताशाही को यदि बिना सुधार किए एआई के हवाले कर दिया जाए, तो समस्या समाप्त नहीं होगी, बल्कि उसका डिजिटल विस्तार हो जाएगा। गलत व्यवस्था को मशीन से चलाने पर वह सही व्यवस्था नहीं बन जाती। यदि पुराना डेटा भेदभावपूर्ण है, तो एआई उसी भेदभाव को नए रूप में आगे बढ़ा सकता है। यदि प्रशासनिक सोच नागरिकों के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो तकनीक संवेदनशीलता पैदा नहीं कर सकती। मशीन के पास गति हो सकती है, लेकिन न्यायबोध, सामाजिक अनुभव और मानवीय विवेक का विकल्प नहीं।

एल्गोरिद्मिक पक्षपात शासन के लिए गंभीर खतरा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, भाषा और आर्थिक स्थिति से जुड़ी असमानताएँ पहले से मौजूद हैं। यदि इन्हीं असमानताओं से प्रभावित आँकड़ों के आधार पर एआई निर्णय लेने लगे, तो वंचित नागरिकों के साथ भेदभाव और अधिक अदृश्य हो सकता है। पहले अन्याय का चेहरा दिखाई देता था, अब वह गणना और तकनीकी प्रक्रिया के पीछे छिप सकता है। किसी व्यक्ति को योजना से बाहर कर दिया जाए और कारण केवल यह बताया जाए कि प्रणाली ने उसे योग्य नहीं पाया, तो यह आधुनिक प्रशासन नहीं, डिजिटल निरंकुशता का नया रूप होगा। निजता के मामले में भी सरकारों को आत्ममंथन करना चाहिए।

नागरिक पहले ही अपनी पहचान, बैंक खाते, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विवरण अनेक सरकारी प्रणालियों में उपलब्ध करा चुके हैं। क्या अब इन जानकारियों को एआई प्रशिक्षण और विश्लेषण के नाम पर अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा? क्या नागरिक की जानकारी पर सरकार का अधिकार असीमित है? डेटा सुरक्षा केवल तकनीकी व्यवस्था का प्रश्न नहीं, नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रश्न है। यदि संवेदनशील जानकारी लीक होती है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल किसी सर्वर या सॉफ्टवेयर पर डालकर समाप्त नहीं की जा सकती।

सबसे चिंताजनक स्थिति जवाबदेही के धुंधले पड़ने की है। सरकारी अधिकारी कह सकता है कि निर्णय प्रणाली के सुझाव पर लिया गया, तकनीकी कंपनी कह सकती है कि उसने केवल उपकरण दिया, और विभाग कह सकता है कि प्रक्रिया स्वचालित थी। अंततः नागरिक किसे जवाबदेह ठहराए? लोकतंत्र में जिम्मेदारी का कोई रिक्त स्थान नहीं हो सकता। मशीन के पीछे छिपकर निर्णय लेने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक उत्तरदायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकारी निर्णय में एआई का इस्तेमाल हुआ है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अंतिम निर्णय किसने लिया और उसके परिणामों की जिम्मेदारी किसकी है। शासन में एआई के उपयोग पर पारदर्शिता कोई कृपा नहीं, नागरिक का अधिकार होना चाहिए। नागरिक को बताया जाए कि उसके आवेदन, शिकायत, पात्रता या किसी अन्य प्रक्रिया में एआई की भूमिका है या नहीं। निर्णय का आधार क्या है, संबंधित जानकारी कहाँ से आई और यदि निर्णय गलत है तो उसे चुनौती देने का रास्ता क्या है–इन सवालों के उत्तर उपलब्ध होने चाहिए।

तकनीकी जटिलता को जवाबदेही से बचने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए स्वतंत्र परीक्षण और लेखा-परीक्षण अनिवार्य होने चाहिए। सरकारी एआई प्रणालियों की नियमित जाँच केवल उनकी गति और लागत बचत के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी सटीकता, निष्पक्षता, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव के आधार पर होनी चाहिए। जिन प्रणालियों का प्रभाव पेंशन, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नागरिक अधिकारों पर पड़ता है, उनमें कठोर निगरानी और मानवीय अनुमोदन अनिवार्य होना चाहिए।

गलत निर्णय की स्थिति में नागरिक को सरल शिकायत व्यवस्था, पुनर्विचार और मानवीय सुनवाई का अधिकार मिले। भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। डेटा का उपयोग सीमित उद्देश्य के लिए हो, अनावश्यक संग्रह से बचा जाए और सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों पर जवाबदेही तय हो। सरकारी कर्मचारियों को भी एआई की सीमाओं, गलत उत्तरों, पूर्वाग्रहों और साइबर खतरों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। केवल तकनीक खरीद लेना डिजिटल शासन नहीं है; उसका विवेकपूर्ण संचालन ही वास्तविक सुधार है।

एक और खतरा डिजिटल विभाजन का है। यदि सरकार धीरे-धीरे सभी सेवाओं को एआई आधारित माध्यमों पर निर्भर कर दे, तो ग्रामीण नागरिक, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, कम डिजिटल साक्षरता वाले लोग और भाषाई रूप से वंचित समुदाय पीछे छूट सकते हैं। नागरिक को सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए मशीन से संवाद करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। तकनीक सुविधा दे, लेकिन मानवीय सहायता का दरवाजा बंद न करे। सरकार को एआई के प्रति न अंधा उत्साह दिखाना चाहिए, न भय के कारण उसे पूरी तरह अस्वीकार करना चाहिए। आवश्यकता संतुलित, नियंत्रित और नागरिक-केंद्रित उपयोग की है। उच्च जोखिम वाले निर्णयों में मानव निगरानी, स्वतंत्र ऑडिट, स्पष्ट जिम्मेदारी, डेटा सुरक्षा और प्रभावी शिकायत निवारण अनिवार्य होना चाहिए। सरकार का उद्देश्य मशीनों से नागरिकों को नियंत्रित करना नहीं, तकनीक से नागरिकों की समस्याएँ हल करना होना चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबाइल : 9210092542 फोन :- 011-46696546 E-mail :

अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा से जुड़ेंगे राम और सीता की जन्मभूमि के तार, भारत-नेपाल संबंधों को मिलेगी मजबूती : सीएम योगी

लखनऊ (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और नेपाल के जनकपुरधाम के बीच सीधी रेल सेवा की शुरुआत को भारत और नेपाल के सदियों पुराने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती देने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि अवध और मिथिला के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं 'रोटी-बेटी' के चिरंतन संबंधों में आज एक नवीन स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के कर-कमलों से सोमवार को प्रभु श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या धाम और माता जानकी की जन्मस्थली जनकपुर धाम के मध्य सीधी रेल सेवा का शुभारंभ होगा। प्रभु श्रीराम की कृपा से त्रेतायुग की स्मृतियों को जीवंत करने वाले इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए मुझे अयोध्या धाम में उपस्थित रहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि युगों से अक्षुण्ण भारत और नेपाल का यह आत्मीय एवं सांस्कृतिक संबंध अब आधुनिक रेल संपर्क से और अधिक सुदृढ़ होगा। यह ऐतिहासिक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 'विरासत भी, विकास भी' और 'नेबरहुड फर्स्ट' के संकल्प का जीवंत प्रमाण है। इससे दोनों देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रा सुगम होगी तथा धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एकात्मता और क्षेत्रीय समृद्धि को भी नई गति मिलेगी। अवध को मिथिला से एकाकार करने वाले इस पावन उपहार के लिए सभी रामभक्तों को हृदय से बधाई! जय श्री सीताराम।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सोमवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या और नेपाल के जनकपुरधाम के बीच नई साप्ताहिक रेल सेवा को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारतीय रेलवे की ओर से शुरू की जा रही इस रेल सेवा का नाम 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' रखा गया है। यह रेल सेवा रामायण से जुड़े दो प्रमुख धार्मिक केंद्रों को सीधे रेल संपर्क से जोड़ेगी। जनकपुरधाम को माता सीता की जन्मस्थली और अयोध्या को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व प्राप्त है। ऐसे में इस रेल सेवा से दोनों देशों के श्रद्धालुओं और यात्रियों को इन महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।

भारतीय रेलवे के अनुसार, सोमवार को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से जनकपुरधाम के लिए उद्घाटन विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। नियमित रेल सेवा का मार्ग और समय-सारिणी रेलवे की ओर से बाद में जारी की जाएगी। इस पहल को भारत और नेपाल के बीच सीमा पार रेल संपर्क के विस्तार के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एकात्मता और द्विपक्षीय मैत्री को प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मां के बिना जीवन से भावनात्मक सुरक्षा और घर की छांव दोनों छिन जाती हैं : योगी



लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि मां केवल जननी नहीं, बल्कि जगत जननी है। ईश्वर की जननी भी मां ही है। मां की ममता दुनिया की सबसे सुंदर भावना है। उन्होंने कहा कि मां वह है, जो हर किसी की जगह ले सकती है, लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता। 'योगी की पाती' में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मां को नमन करते हुए लिखा कि मां के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है।

मां के कारण ही हमारा अस्तित्व है। प्रभु श्रीराम के वनगमन के समय मां कौशल्या का आशीर्वाद, भगवान श्रीकृष्ण का मां की इच्छा से मथुरा के कारावास से गोकुल जाना और मां के संस्कारों से बालक ध्रुव एवं प्रह्लाद का महान व्यक्तित्व बनना मातृत्व की महत्ता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने अपने संन्यास जीवन से जुड़ा भावुक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि जब उनकी प्रथम गुरु और उन्हें अक्षर ज्ञान देने वाली पूज्य मां अनंत यात्रा पर निकल गईं, तो उन्हें संन्यास ग्रहण करने के तीन वर्ष से अधिक समय बाद की वह घटना याद आ गई, जब वह भगवा वस्त्र धारण कर अपने घर की दहलीज पर पहुंचे थे। उन्होंने लिखा कि गोरखपुर से पंचूर तक की उस यात्रा में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। संन्यास परंपरा के महत्वपूर्ण विधान के अनुसार उन्होंने घर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई।

जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

लखनऊ (एजेंसी)



कर्तव्य पथ पर अग्रसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 'जनता दर्शन' में अलग भूमिका में दिखे। उनके पास कक्षा-8 का छात्र प्रिंस क्रिकेट खेलने के लिए आर्थिक सहायता और कोचिंग उपलब्ध कराने की फरियाद लेकर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर 4-5 मिनट तक पास खड़े होकर काउंसलिंग की। सीएम योगी ने कहा- बेटा तुम्हारा नाम प्रिंस है, इसलिए पढ़-लिखकर 'प्रिंस' बनो। हम क्रिकेट में भी तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे।

मुख्यमंत्री 'जनता दर्शन' में कुर्सियों पर बैठाए गए हर व्यक्ति तक पहुंचे, एक-एक कर उनके प्रार्थना पत्र लिए, फिर समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री ने पास में खड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए। गोंडा के इटियाथोक के पड़री पारासराय गांव निवासी प्रिंस साहू कक्षा-8 में पढ़ता है। वह सोमवार को 'जनता दर्शन' में पहुंच गया। लोगों की फरियाद सुनते-सुनते मुख्यमंत्री प्रिंस के पास पहुंचे। बच्चे को देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने का कारण पूछा, जिस पर प्रिंस ने बताया कि उसके अंदर बचपन से ही क्रिकेट खेलने का जुनून है।

वह क्रिकेट में नाम कमाना चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस भरने और किट खरीदने में असमर्थ है। इस पर मुख्यमंत्री ने उसकी काउंसलिंग की, कहा कि बेटा अभी कक्षा-8 में हो। खेलने के साथ-साथ मन लगाकर पढ़ाई भी करो और अच्छे नंबरों से यह सत्र उत्तीर्ण करो, फिर हम आपका एडमिशन क्रिकेट की कोचिंग में करा देंगे। मुख्यमंत्री ने समस्या लेकर पहुंचे लोगों से कहा कि चिंता मत करिए। सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराएगी। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा।

बिहार : भाइयों के घरों में लगी भीषण आग, कपड़े-गहने और नकदी समेत लाखों का नुकसान



किशनगंज (एजेंसी)

गलगलिया थाना क्षेत्र के भातगांव पंचायत अंतर्गत भोकसरभीट्ठा गांव के वार्ड संख्या-4 में अचानक लगी भीषण आग से तीन भाइयों के मकान जलकर राख हो गए। अगलगी में घरों में रखे कपड़े, बर्तन, अनाज, सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेत लाखों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। घटना के बाद तीनों परिवारों के सामने रहने और खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी सैईद अख्तर और उनके दो भाइयों के मकानों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तीनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया। मकानों से आग की ऊंची लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गलगलिया थानाध्यक्ष रवि शंकर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद अग्निशमन वाहन और ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक तीनों मकानों में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही भातगांव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बृजमोहन उर्फ मुन्ना ने गांव से बाहर रहने के बावजूद दूरभाष पर ठाकुरगंज के अंचलाधिकारी से बात की। उन्होंने अंचल कर्मियों को घटनास्थल पर भेजकर अगलगी से हुई क्षति का आकलन कराने और सरकारी प्रावधानों के तहत पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की पहल की। मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि वह फिलहाल गांव से बाहर हैं, लेकिन जल्द ही पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। साथ ही अपने स्तर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है।

काशी में हिंदू-मुस्लिम बहनें मिलकर बना रहीं गोबर के दीये, देव दीपावली पर एक लाख दीये बांटने का लक्ष्य

वाराणसी (एजेंसी)



काशी में सांप्रदायिक सद्भाव और महिला सशक्तीकरण की एक अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। समाज सेविका उमा वानु मुस्लिम महिलाओं और दिव्यांग बच्चों की मदद से हिंदू त्योहारों के लिए गाय के गोबर से पर्यावरण के अनुकूल दीये बनवा रही हैं। उनका लक्ष्य काशी के 7-8 घाटों पर 50,000 से 1 लाख दीये वितरित करना है। राष्ट्रीय पसमांदा सेवा समिति के महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुर्शीदा बानो ने कहा, 'हम सभी हिंदू-मुस्लिम बहनें मिलकर काम कर रही हैं। एक रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, दिव्यांग बच्चे भी काम कर रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी काम हो रहा है। गंगा-जमुनी तहजीब के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने करीब एक लाख दीये बनाने का टारगेट रखा है, जिसमें से 10,000 दीये बन चुके हैं। देव दीपावली को लेकर हमने यह खास प्रण लिया था। घाट-घाट जाकर हम दीया वितरण करेंगे।' उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चीज रोजगार है। इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं कि रोजगार भी हो जाए और हिंदू-मुस्लिम एकता को लेकर मिसाल भी पेश कर रहे हैं। हम बंटे नहीं हैं, बल्कि एक साथ मिलकर भाईचारे और मोहब्बत का काम कर रहे हैं। वाराणसी की समाजसेवी उमा बानो ने कहा, हमारा मुल्क अपने आप में एक पहचान है। जिस मुल्क को हम सलामी देते हैं। हम हर त्योहार में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मुस्लिम बहनों ने मिलकर गाय के गोबर का दीया बनाया है। हिंदू आस्था के अनुसार गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है।

बिहार : खेत की जुताई को लेकर तलवार-फरसा से हमले में 4 घायल, ट्रैक्टर में भी लगाई आग

सारण (एजेंसी)



सारण के तरैया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लौवा गांव में खेत की जुताई करने से रोकने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट और हमले में बदल गया। इस दौरान चार लोग घायल हो गए और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार, लौवा गांव में जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी बीच खेत की जुताई को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने खेत की जुताई करने से मना किया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने तलवार, फरसा और लाठी से हमला कर दिया। अचानक हुई हिंसा में चार लोग जख्मी हो गए। इसी दौरान एक ट्रैक्टर में भी आग लगा दी गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। इस घटना में घायल लोगों की पहचान शैलेन्द्र सिंह, विवेक सिंह, विक्रांत सिंह और सौरव सिंह के रूप में हुई है।

सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका उपचार जारी है। मामले में पीड़ित पक्ष ने उमेश सिंह, मंटू सिंह, मदन सिंह, मनीष सिंह और सोनू सिंह समेत परिवार के करीब 25 अज्ञात लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, हमलावरों ने तलवार, फरसा और लाठी से मारपीट की। ट्रैक्टर में आग लगाने का आरोप भी लगाया गया है। घटना के बाद लौवा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसा से स्थानीय लोगों में चिंता है। पुलिस मामले की जांच और शिकायत में लगाए गए आरोपों के सत्यापन में जुटी है। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और आगे की कार्रवाई का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।

कटिहार में पप्पू यादव की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट, पांच लोग घायल, सांसद सुरक्षित

कटिहार (एजेंसी)

बिहार के कटिहार जिले में रविवार देर रात पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के काफिले के साथ बड़ा सड़क हादसा हो गया। कटिहार से सालमारी जाने के दौरान काफिले में शामिल कटिहार पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए। हालांकि, सांसद पप्पू यादव पूरी तरह सुरक्षित हैं। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, पप्पू यादव पूर्णिया से सालमारी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान बेलोरी-सन्हौली-सालमारी मुख्य सड़क पर कुम्हरी के पास निर्माणाधीन पुल के समीप उनके काफिले के आगे चल रही पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके बाद गाड़ी सड़क किनारे स्थित गड्ढे में जा गिरी। हादसे के समय एस्कॉर्ट वाहन में सुरक्षाकर्मी सवार थे। दुर्घटना में पांच लोगों को चोटें आई हैं। घटना के बाद घायलों को तत्काल इलाज के लिए भेजा गया। फिलहाल, एस्कॉर्ट गाड़ी के अनियंत्रित होने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। निर्माणाधीन पुल के पास सड़क की स्थिति या किसी अन्य वजह से हादसा हुआ, इसकी जानकारी सामने आनी बाकी है। दुर्घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में पांच लोगों को चोटें आई हैं। किसी के गर्दन, किसी के माथे तो किसी के पीठ में चोट लगी है। सभी घायलों को उचित इलाज के लिए भेजा गया है। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई।

विवादित जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला, पूर्व सीओ और राजस्व कर्मचारी समेत कई पर एक और प्राथमिकी

मुज्जफरपुर (एजेंसी)



विवादित भूमि की अवैध रूप से जमाबंदी कायम करने और गलत लगान रसीद जारी करने के मामले में अंचल के पूर्व अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमीन फर्जीवाड़े के आरोपी तत्कालीन अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल और तत्कालीन राजस्व कर्मचारी करुण करण के खिलाफ नगर थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज हुई है। जमानत पर बाहर चल रहे दोनों आरोपियों पर जिलाधिकारी को गलत सूचना देकर गुमराह करने का भी गंभीर आरोप है।

मिठनपुरा के चर्च रोड निवासी पंकज कुमार के आवेदन पर नगर थाना पुलिस ने तत्कालीन अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, मीना कुमारी तथा अन्य लोगों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पीड़ित पंकज कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनके दिवंगत पिता कामदेव मंडल की स्वअर्जित जमीन पर संयुक्त परिवार का मकान बना है। इस भूमि और मकान के स्वामित्व को लेकर सिविल कोर्ट में स्वत्व वाद लंबित चल रहा है। इसके अलावा भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्वी के न्यायालय में भी दाखिला-खारिज से जुड़ा अपील वाद विचाराधीन है। इसके बावजूद अधिकारियों ने मिलीभगत कर 6 दिसंबर, 2025 को म्यूटेशन वाद में नियम विरुद्ध शुद्धि पत्र निर्गत कर दिया। इसी शुद्धि पत्र के आधार पर मीना कुमारी के नाम जमाबंदी दर्ज कर 4 अप्रैलको लगान रसीद काट दी गई। इससे पूर्व मीना कुमारी की ओर से प्रस्तुत दो म्यूटेशन आवेदनों को खारिज किया जा चुका था।

मामले में हुई गंभीर धांधली को लेकर शिकायतकर्ता के बड़े भाई केशव कुमार ने 17 जुलाई को जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि शिकायत के बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी ने 6 अगस्त 2026 को जिलाधिकारी को भेजे गए अपने जांच प्रतिवेदन में इस म्यूटेशन वाद को आदेश के लिए प्रक्रियाधीन बताया। जबकि सच यह था कि प्रतिवेदन भेजने से कई महीने पहले ही शुद्धि पत्र जारी करके अवैध जमाबंदी और रसीद निर्गत करने की पूरी प्रक्रिया की जा चुकी थी।

इस प्रकार प्रशासनिक पद का अनुचित लाभ उठाते हुए उच्चाधिकारियों को अंधेरे में रखा गया। आवेदक ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वास्तविक तथ्यों को छिपाने की सुनियोजित साजिश रची, ताकि दूसरे पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। नगर थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया है।

कार्तिक पूर्णिमा : 24 नवंबर को पटना में इन रास्तों पर रहेगी नो एंट्री

पटना (एजेंसी)

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने इसके लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इसके तहत कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी, जबकि श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग घाटों के आसपास पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करें और यातायात नियमों का पालन करें। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक, आज कारगिल चौक से पूर्वी दिशा में गायघाट तक किसी भी तरह के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से गायघाट पुल के नीचे तक सभी इंट्री प्वाइंट बंद रहेंगे। हालांकि, खजांची रोड से पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों को पार्किंग की अनुमति दी जाएगी। कारगिल चौक से पश्चिम में शाहपुर घाट तक सभी प्रकार के वाहन चल सकेंगे। गायघाट की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को पुरानी बाइपास या न्यू बाइपास से सीधे धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर अथवा बिरकोन गोलंबर के रास्ते गायघाट की ओर जाना होगा। वहां निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े करने होंगे। गायघाट पुल के नीचे टेंपो और अन्य व्यावसायिक वाहनों के आने-जाने पर भी विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। पटना सिटी की ओर से आने वाले व्यावसायिक वाहन एनएमसीएच तक जा सकेंगे। धनुकी मोड़ और बिरकोन गोलंबर से आने वाले वाहनों के लिए भी अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। इसमें शाहपुर घाट, पीपापुल घाट, दीघा घाट, राजीव नगर, कुर्जी घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, मीनार घाट, गायघाट और पटना सिटी क्षेत्र के घाट शामिल हैं।

नोएडा के सेक्टर-6 में प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी में भीषण आग

नोएडा (एजेंसी)



नोएडा के सेक्टर-6 स्थित एक निजी कंपनी में देर रात अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई। कंपनी में प्लास्टिक से सजावटी सामान (डेकोरेटिव आइटम) बनाने का काम किया जाता है। प्लास्टिक से बने उत्पाद और अन्य सामग्री मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार, थाना फेस-1 क्षेत्र के सेक्टर-6 में स्थित निजी कंपनी में देर रात अचानक आग लग गई। शुरुआत में कंपनी के अंदर से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दीं। कुछ ही देर में आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग को तत्काल सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी की बौछार की गई।

कंपनी में प्लास्टिक से सजावटी सामान तैयार किया जाता है। ऐसे में परिसर में प्लास्टिक से बनी सामग्री और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं मौजूद होने के चलते आग तेजी से फैल गई। पूरी बिल्डिंग में आग फैलने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल कर्मियों ने कई घंटों तक अभियान चलाकर आग पर काबू पाया। आग बुझाए जाने के बाद भी किसी प्रकार की दोबारा आग लगने की आशंका को खत्म करने के लिए दमकल विभाग की ओर से कूलडाउन (कूलिंग) प्रक्रिया जारी रखी गई। इस दौरान बिल्डिंग के अंदर मौजूद गर्म हिस्सों और आग से प्रभावित स्थानों पर पानी डालकर उन्हें ठंडा किया जा रहा है ताकि अंदर सुलग रही आग दोबारा न भड़क सके। इस घटना में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि, आग की चपेट में आने से कंपनी की बिल्डिंग और उसमें रखे सामान को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जाना बाकी है।

सरयू-कमला एक्सप्रेस के शुभारंभ पर इकबाल अंसारी ने जताई खुशी, बोले-श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा

अयोध्या (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम को जोड़ने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस के शुभारंभ पर अयोध्या के इकबाल अंसारी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन अयोध्या के लिए बेहद शुभ है क्योंकि यह भारत से नेपाल तक जाएगी।

इससे दोनों देशों के बीच न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि आपसी संबंध भी और मजबूत होंगे। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या की धरती भगवान श्रीराम की नगरी रही है। अब यहां से सीतामढ़ी तक ट्रेन जाने से दोनों स्थानों का जुड़ाव और गहरा होगा। इससे विकास को गति मिलेगी, लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और यात्रियों को तमाम सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज वह दिन आ गया है, जब अयोध्या से ट्रेन नेपाल तक जाएगी। इसके लिए हिंदू और मुसलमान, सभी की ओर से बधाई और धन्यवाद दिया जा रहा है। इकबाल अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे ही होने चाहिए, जिनके प्रयासों से एक देश दूसरे देश से जुड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बेहतर संबंधों का ही परिणाम है कि आज सीतामढ़ी के लिए ट्रेन अयोध्या से चल रही है। यह ट्रेन दोनों देशों के लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे को भी बढ़ाएगी। बता दें कि सरयू-कमला एक्सप्रेस का शुभारंभ सोमवार को अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा के रूप में किया जा रहा है।

इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या की धरती भगवान श्रीराम की नगरी रही है। अब यहां से सीतामढ़ी तक ट्रेन जाने से दोनों स्थानों का जुड़ाव और गहरा होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह इसे वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे जबकि आम यात्रियों के लिए नियमित सेवा 28 नवंबर से शुरू होगी। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। यह रेल सेवा उत्तर प्रदेश की अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम को सीधे जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

दोनों शहरों का रामायण परंपरा में विशेष स्थान है। जनकपुर धाम को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है जबकि अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में पूरे विश्व में श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में यह रेल संपर्क केवल दो शहरों के बीच आवागमन का साधन नहीं है बल्कि दोनों देशों की साझा धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाला माध्यम भी बनेगा।

अमेरिकी हाउस का एजेंडा तय, कांग्रेस सदस्य बोले- ईरान युद्ध, टैरिफ और हेल्थकेयर पर होगी सबसे पहले चर्चा

वाशिंगटन (एजेंसी)



जनवरी में नई कांग्रेस का होगा गठन, डेमोक्रेट्स के स्पीकर पद उम्मीदवार जेफरीज ने कांग्रेस सदस्यों द्वारा स्टॉक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने का रखा प्रस्ताव, उन्होंने हेल्थकेयर, इमिग्रेशन और जीवन-यापन की लागत जैसे मुद्दों पर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की संभावना तलाशने की बात भी कही

अमेरिकी हाउस में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने कहा कि ईरान युद्ध को खत्म करना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ मुद्दे को सुलझाना, और हेल्थकेयर को लेकर सवाल हाउस में उनकी पार्टी के शुरुआती एजेंडा में शामिल होगा। जनवरी में नई कांग्रेस का गठन होगा। डेमोक्रेट्स के स्पीकर पद उम्मीदवार जेफरीज ने कांग्रेस सदस्यों द्वारा स्टॉक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा।

साथ ही, उन्होंने हेल्थकेयर, इमिग्रेशन और जीवन-यापन की लागत जैसे मुद्दों पर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की संभावना तलाशने की बात भी कही। सीबीएस के 'फेस द नेशन' कार्यक्रम में उन्होंने किसी ऐसे विशेष बिल का नाम नहीं बताया जिसे डेमोक्रेट्स सबसे पहले पेश करेंगे। इसके बजाय, उन्होंने एक ऐसा एजेंडा सामने रखा जो मुख्य रूप से 'खर्चे' और 'जवाबदेही' पर केंद्रित है। जेफरीज ने कहा, हमें जीवन-यापन की बढ़ती लागत को कम करना होगा। जीवनशैली बहुत महंगी हो गई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं; वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं।

उन्होंने ईरान संघर्ष को भी उन मुद्दों में शामिल किया जिन पर उनके मुताबिक तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें ईरान में छेड़े गए इस गैर-जिम्मेदाराना और महंगे संघर्ष को खत्म करना होगा, जिसकी वजह से गैस, भोजन और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमें मेडिकेड में की गई कटौती को वापस लेना होगा और स्नैप (सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम) के तहत मिलने वाले लाभों को फिर से बहाल करना होगा। 'मेडिकेड' कम आय वाले पात्र लोगों को हेल्थ कवरेज प्रदान करता है, जबकि 'सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम' (जिसे स्नैप के नाम से जाना जाता है) पात्र परिवारों को भोजन खरीदने में मदद करता है। जेफरीज ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ (आयात शुल्क) पर भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इन टैरिफ की वजह से अमेरिकियों के लिए खर्च बढ़ गया है।

उन्होंने 'अफोर्डेबल केयर एक्ट' के तहत मिलने वाले टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने की भी वकालत की, जो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाने में मदद करते हैं। उन्होंने किसी विशेष टैरिफ दर या उन देशों का नाम नहीं बताया, जिनके निर्यात पर इस प्रस्तावित कार्रवाई का असर पड़ सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप अपने ही लाए गए टैक्स और खर्च संबंधी कानून के कुछ हिस्सों को पलटने वाले किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, तो जेफरीज ने इस बात को खारिज कर दिया कि डेमोक्रेट्स केवल कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए बिल तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, नहीं, हम ऐसे बड़े, प्रभावशाली और सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसकी मांग अमेरिकी जनता कर रही है। जेफरीज ने इस साल की शुरुआत में हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने के लिए हाउस (सदन) में मिली दोनों पार्टियों (डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन) के समर्थन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ अमेरिकियों को हर महीने 1,000 डॉलर से भी ज्यादा प्रीमियम बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप मेडिकेड में की गई कटौती को वापस लेने के फैसले पर वीटो (रोक) लगा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया: 'देखिए, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।'

इसके बावजूद, उन्होंने किफायती खर्च, स्वास्थ्य सेवा और आव्रजन (इमिग्रेशन) को ऐसे क्षेत्रों के रूप में पहचाना, जहां डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति और रिपब्लिकन के साथ मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाश सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली खराब हो चुकी है। हमें इसे ठीक करने की जरूरत है। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम केवल पुरानी स्थिति में वापस न लौटें, बल्कि मौजूदा हालात से कहीं बेहतर स्थिति बनाएं। और हमें अपनी खराब हो चुकी आव्रजन प्रणाली को भी ठीक करने की जरूरत है।

पाकिस्तान की सेना को अमेरिकी फंडिंग क्यों, नवनिर्वाचित सीनेटर अल सैयद ने उठाए सवाल

वॉशिंगटन (एजेंसी)



अमेरिका के नवनिर्वाचित सीनेटर अब्दुल अल सैयद ने पाकिस्तानी सेना को अमेरिकी फंडिंग का विरोध किया है। उन्होंने यह टिप्पणी इजरायल की धार्मिक पहचान और सभी नागरिकों के समान अधिकारों से जुड़ी बहस के दौरान की। मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के नवनिर्वाचित सीनेटर अल सैयद ने रविवार को एनबीसी के कार्यक्रम 'मीट द प्रेस' में कहा, 'मेरा मानना है कि हमें पाकिस्तान की सेना को वित्तीय सहायता देने के कारोबार में भी नहीं होना चाहिए।'

उनकी यह टिप्पणी उस समय आई, जब कार्यक्रम की मेजबान क्रिस्टन वेलकर ने उनसे सवाल किया कि यदि वह धार्मिक या जातीय पहचान के आधार पर बने देशों का विरोध करते हैं तो फिर पाकिस्तान और डेनमार्क जैसे देशों के संदर्भ में उनका क्या रुख है। उनसे यह भी पूछा गया कि इजरायल को यहूदी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान क्यों छोड़नी चाहिए? इस पर अल सैयद ने कहा, मैं सामान्य तौर पर ऐसे राष्ट्रों के पक्ष में नहीं हूं, जिनकी पहचान किसी एक जातीय समुदाय पर आधारित हो। मैं महज अपने सिद्धांतों को सभी देशों पर समान रूप से लागू करने की बात कर रहा हूं। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां नागरिकों के साथ उनकी त्वचा के रंग या उनके पूजा करने के तरीके के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सरकार जिन देशों को सहायता देती है, उनसे भी समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हमें हमेशा हर चीज से ऊपर लोकतंत्र को रखना चाहिए।

यमन के हूती का दावा, 'सऊदी ऑयल रिफाइनरी और रडार सिस्टम को बनाया निशाना'

सना (एजेंसी)



यमन के हूती समूह ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। उनके मुताबिक, सऊदी अरब के लाल सागर तट पर स्थित एक तेल रिफाइनरी और राजधानी रियाद के दक्षिण में मौजूद एक रडार फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब सीमा पार शत्रुता बढ़ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट किए बयान में, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि दो अभियान चलाए गए थे। पहले ऑपरेशन में लाल सागर तट पर स्थित राबिघ तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, और दावा किया कि यह 'सीधा निशाना' (डायरेक्ट हिट) था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे ऑपरेशन में रियाद के दक्षिण में वादी अद-दवासिर स्थित एक रडार केंद्र को दो चरणों में निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि इस ऑपरेशन में काफी सफलता मिली। सरिया ने इस्तेमाल किए गए हथियारों या हुए नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। हाल के दिनों में, हूती लड़ाकों ने सऊदी हवाई अड्डों, तेल प्रतिष्ठानों और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। वहीं, हूती मीडिया ने यमन भर में सऊदी हवाई हमलों के तेज होने की खबर दी है। ये ऑपरेशन ऐसे समय में हुए हैं जब हूती और सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन वाली यमन की सरकारी सेनाओं के बीच लड़ाई तेज हो गई है। हूती-संचालित 'अल-मसीराह टीवी' की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले शनिवार शाम को सऊदी लड़ाकू विमानों ने यमन के लाल सागर बंदरगाह शहर होदेइदाह में कई हवाई हमले किए। चैनल ने इन हमलों को 'सऊदी आक्रामकता' करार दिया, लेकिन इसमें हताहतों या नुकसान के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया। एक स्थानीय निवासी ने सिन्हुआ को बताया कि शहर में पांच से अधिक जोरदार धमाके हुए, जबकि लड़ाकू विमान ऊपर उड़ान भरते रहे। निवासी ने कहा, धमाके बहुत तेज थे, और हम अभी भी अपने ऊपर विमानों की आवाज सुन सकते थे।

ईरान पर हमले से भड़क सकता है बड़ा क्षेत्रीय युद्ध, आईडीएफ ने बेंजामिन नेतन्याहू को दी चेतावनी : रिपोर्ट

यरूशलम (एजेंसी)



इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने 'प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान पर हमले की स्थिति में सामने आने वाले नतीजे से रूबरू कराया है। चेतावनी दी है कि ईरान पर हमले से एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ सकता है। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की एक रिपोर्ट में इसका उल्लेख है।

टेलीविजन नेटवर्क 'चैनल 12' की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि, पिछले हफ्ते नेतन्याहू और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के बीच एक बंद कमरे में हुई बैठक में इसके नतीजे पर प्रकाश डाला गया। कथित तौर पर इस समय ईरान के खिलाफ अपने सैन्य विकल्पों पर इजरायल गंभीरता से विचार कर रहा है। सैन्य खुफिया विभाग ने चेतावनी दी है कि इजरायल के हमले से लेबनान, सीरिया और गाजा सहित 'कई मोर्चों' पर संघर्ष छिड़ सकता है। यह नेतन्याहू और इजरायल की खुफिया एजेंसी 'मोसाद' के उस अनुमान के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि यह अभियान तीन से पांच दिनों तक ही सीमित रह सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विपक्षी नेता एविग्डोर लिबरमैन ने हाल ही में इस बात का संकेत दिया था कि नेतन्याहू अमेरिका की मंजूरी के बिना ही एकतरफा हमला कर सकते हैं। लिबरमैन ने पिछले हफ्ते कहा था कि इस समय इजरायल का कोई भी हमला अनुचित होगा और यह 'पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित' होगा।

आईडीएफ ने बंद कमरे की बैठकों में की गई चर्चा पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एक अज्ञात सूत्र के हवाले से (प्रसारक 'कान' की रिपोर्ट) कहा गया है कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर 'जल्द से जल्द' हमला करने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि, राष्ट्रपति ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और बताया जा रहा है कि वे ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं। इस महीने की शुरुआत में, नेतन्याहू ने एक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने की अपनी मांग दोहराई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रहा है और केवल एक व्यापक गठबंधन ही इजरायल के लिए मौजूद इस खतरे को खत्म कर सकता है। पहले से रिकॉर्ड किए गए एक संबोधन में, नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट से आग्रह किया (जिन्हें इज़राइल की अगली सरकार बनाने का काम सौंपा गया है) कि वे बिना किसी पूर्व शर्त के गठबंधन वार्ता में शामिल हों। नेतन्याहू ने कहा, 'ईरानी शासन, जो इजरायल को नष्ट करना चाहता है, एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है।

जम्मू-कश्मीर : जंगल-पहाड़ों में अब नहीं टूटेगा जवानों का संपर्क, बिना नेटवर्क भी भेज सकेंगे संदेश और लोकेशन

जम्मू (एजेंसी)

जम्मू-कश्मीर के दुर्गम जंगलों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज होंगे। सेना 50 विशेष संचार उपकरण खरीदने जा रही है। इससे दुर्गम इलाकों में सर्च अभियान के दौरान भी जवानों का संपर्क नहीं टूटेगा। वे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट के बिना एक-दूसरे को गतिविधियों के संदेश और अपनी लोकेशन साझा कर सकेंगे।

लोरा और मेश नेटवर्क तकनीक से लैस ये उपकरण एक-दूसरे के माध्यम से संदेश आगे पहुंचाने में सक्षम होंगे। एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक 10 से 18 किलोमीटर की संचार क्षमता होगी। इससे दुर्गम इलाकों में अभियान चला रही छोटी-छोटी सैन्य टुकड़ियों के बीच संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी। सेना इन उपकरणों को कम्युनिकेशन नोड (संचार इकाई) नाम दे रही है। ये लोरा और मेश नेटवर्क तकनीक पर आधारित होंगे। इसमें प्रत्येक उपकरण नेटवर्क की एक कड़ी के रूप में काम करेगा। यदि दो जवानों के बीच सीधे संपर्क में बाधा आती है तो उनके बीच मौजूद तीसरा उपकरण संदेश को आगे पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इस प्रक्रिया को मल्टीहॉप कम्युनिकेशन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर अतिरिक्त रिले नोड लगाकर संचार की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी। इससे दूर-दराज के इलाकों में तैनात जवानों के बीच भी संपर्क बनाए रखना आसान होगा। संदेशों की सुरक्षा के लिए एईएस-256 एन्क्रिप्शन या इसके समकक्ष सुरक्षित प्रणाली उपलब्ध होगी। जवान व्यक्तिगत संदेश भेजने के अलावा समूह और अलग-अलग चैनलों पर भी संवाद कर सकेंगे। यह व्यवस्था इंटरनेट के बिना भी काम करेगी। अवंतिपोरा स्थित 15 कोर की सिग्नल ब्रांच के लिए इन 50 उपकरणों की खरीद की जाएगी।

बाबा का वैष्णव तिलक से हुआ श्रृंगार, मुकुट और मुंडमाला किया धारण, जय श्री महाकाल से गूंजा मंदिर

उज्जैन (एजेंसी)



एमपी : रात में महाकाल पहुंचे गोपाल मंदिर, विष्णु को सौंपा सृष्टि का कार्यभार, सुबह वैष्णव तिलक लगाकर दिए दर्शन

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का मनमोहक श्रृंगार किया गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा का विशेष श्रृंगार कर भस्म रमाई गई। आज के श्रृंगार की खास बात यह रही कि बाबा महाकाल को वैष्णव तिलक लगाया गया। चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कर बाबा ने भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। इस दौरान मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर बाबा महाकाल का विशेष पूजन और श्रृंगार किया गया। सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडे-पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी-देवताओं का पूजन किया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया।

दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से तैयार पंचामृत अर्पित कर बाबा का अभिषेक किया गया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कराई गई। फिर वैष्णव तिलक लगाकर उनका आकर्षक श्रृंगार किया गया और भस्म रमाई गई। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

भक्तों ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष किया। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।

रात में देवाधिदेव महादेव ने सवारी के रूप में गोपाल मंदिर पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण (श्री हरि) को सृष्टि के संचालन का कार्यभार सौंपा। वहीं, सुबह महाकाल मंदिर की भस्म आरती में भगवान विष्णु के पूजन के साथ हरिहर मिलन का अलौकिक दृश्य साकार हुआ। इस दिव्य परंपरा के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी की रात 11 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से हरिहर भेंट की पारंपरिक सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल श्री मनमहेश स्वरूप में रजत पालकी में विराजमान होकर महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा और पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचे।

गुजरात हादसा : कोटद्वार पहुंचे जवानों के पार्थिव शरीर, मासूम बेटी समेत अपनों के शव देख बिलख पड़े परिजन

कोटद्वार (एजेंसी)

गुजरात के कच्छ में हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दो सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के पार्थिव शरीर सोमवार तड़के सेना के वाहनों से कोटद्वार के कौड़िया स्थित सेना के कैंप में लाए गए। यहां से तिरंगे में लिपटे सैनिकों के पार्थिव शरीर और उनके परिजनों के शव उनके आवासों पर पहुंचाए गए। अपनों के शव देखते ही परिजन उनसे लिपटकर बिलख पड़े। हादसे में तीन परिवारों के छह सदस्यों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।

द्वितीय गढ़वाल राइफल्स में तैनात नायक सौरभ सिंह नेगी (30), उनकी पत्नी सविता नेगी (30) और तीन माह की मासूम बेटी शिविका के पार्थिव शरीर पदमपुर सुखरो के ध्रुवपुर स्थित उनके आवास पर ले जाए गए। यहां गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने उन्हें सलामी दी। उनके शव मोहल्ले में पहुंचते ही उपस्थित जनसमुदाय रो पड़ा। वहीं, नायक नितिन गुसाईं की पत्नी रिंकी गुसाईं (30) और चार साल की बेटी वामिका के शव मोटाढाक के शिवराजपुर स्थित आवास पर पहुंचाए गए। मां और बेटी के शव देखते ही परिजन फफक पड़े। परिवार के सदस्यों को रोता देख गांव के लोगों की आंखें भी नम हो गईं। हादसे में द्वितीय गढ़वाल राइफल्स में तैनात नायक राजेश सिंह रावत (34) और उनकी आठ वर्षीय बेटी रक्षिता की भी जान चली गई। सेना के जवान उनके पार्थिव शरीर लेकर सिमलचौड़ स्थित आवास पहुंचे तो वहां भी चीख-पुकार मच गई। हर कोई इस हृदयविदारक घटना से स्तब्ध नजर आया। बताया जा रहा है कि तीनों परिवारों के अंतिम दर्शनों के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम ले जाया जाएगा। यहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

'पहले माफी मांगो, फिर आओ तेलंगाना' भाजपा के शीर्ष नेताओं के दौरे पर बोले पोन्नम प्रभाकर

हैदराबाद (एजेंसी)



भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 23 नवंबर को तेलंगाना के करीमनगर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा और जनसभा में शामिल होंगे जबकि 24 और 25 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के भी राज्य में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इन लगातार दौरों को लेकर तेलंगाना की सियासत गरमा गई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को पहले तेलंगाना की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद ही राज्य में आकर लोकतंत्र की बात करनी चाहिए। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले तेलंगाना के गठन को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के लिए राज्य की जनता से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेलंगाना में स्वागत है, लेकिन उन्हें आने से पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले बारह वर्षों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना को क्या दिया है। पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि आज तेलंगाना की जनता भारी परेशानियों का सामना कर रही है।

हाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ से किसानों और आम लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र ने अब तक केंद्रीय टीम क्यों नहीं भेजी और प्रभावित लोगों की मदद के लिए धन क्यों जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों का जवाब देना होगा। मंत्री ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ' यात्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नारा पहले से ही 'संविधान बचाओ' रहा है। आज भाजपा भी उसी नारे पर यात्रा निकाल रही है, यह खुशी की बात है। इससे यह साबित होता है कि भाजपा भी मान रही है कि देश में आज संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। विपक्ष जो बात लंबे समय से कह रहा था, आज भाजपा भी वही गीत गा रही है। पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने दिनों तक केवल 'मन की बात' सुनाई है, अब उन्हें 'जन की बात' भी सुननी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को भाजपा नेताओं के तेलंगाना आने पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तेलंगाना भी भारत का ही एक राज्य है और लोकतंत्र में हर किसी को आने का अधिकार है।

हिमाचल: आधार सीडिंग नहीं करवाई तो अटक सकती है छात्रवृत्ति की राशि, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

शिमला (एजेंसी)



छात्रवृत्ति की राशि का इंतजार कर रहे मेधावी विद्यार्थियों के लिए जरूरी सूचना है। अगर बैंक खाते की आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग पूरी नहीं करवाई गई तो छात्रवृत्ति की रकम खाते में पहुंचने में बाधा आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 2025-26 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों की राशि तकनीकी कारणों से खातों में नहीं पहुंच पा रही है। शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को बैंक खाते की आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग करवाने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के अनुसार, इन प्रक्रियाओं के अधूरे रहने के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि भेजने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में पात्र विद्यार्थियों को बिना देरी किए संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर अपने खाते की आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग पूरी करवानी होगी। बैंक खाते की मैपिंग सुनिश्चित होने के बाद ही छात्रवृत्ति की राशि सीधे खाते में पहुंचने का रास्ता साफ होगा।

इन छात्रवृत्ति योजनाओं के विद्यार्थियों को करना होगा प्रक्रिया पूरी

इस प्रक्रिया से स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) और टीएस नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के पात्र विद्यार्थी प्रभावित हो सकते हैं। टीएस नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

कांग्रेस का पुराना इतिहास काले धन से जुड़ा, 1977 में कारोबारियों से लिए गए थे 113 करोड़ : निशिकांत दुबे

रांची (एजेंसी)



झारखंड के गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पिछले कई दशकों से कारोबारियों से अवैध सांठगांठ और काले धन के इस्तेमाल से चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर 70 के दशक में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर की पुरानी कटिंग साझा की। इसके आधार पर दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1977 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए कारोबारियों से 113 करोड़ रुपये लिए थे। निशिकांत दुबे के मुताबिक, उस समय खर्च की गई यह रकम आज के मूल्य के हिसाब से करीब 25 हजार करोड़ रुपये बैठती है। दुबे ने पुरानी खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान लोकसभा के प्रत्येक उम्मीदवार को दो लाख रुपये और दो जीप उपलब्ध कराई गई थीं। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी चंदे और कारोबारी हितों के बीच पुराने गठजोड़ का आरोप लगाया और इसे देश की राजनीति का काला इतिहास बताया। निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर 'कांग्रेस का काला अध्याय' नाम से शृंखलाबद्ध अभियान चला रहे हैं। इसकी 252वीं कड़ी में उन्होंने लिखा कि 23 नवंबर 1978 को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की एक रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हुई थी।

उनके अनुसार, इस रिपोर्ट में इंदिरा गांधी और कारोबारियों के बीच कथित सांठगांठ का खुलासा किया गया था। दुबे ने सबसे अधिक चंदा देने का आरोप आरपी गोयनका पर लगाया। उन्होंने दावा किया कि गोयनका को तीन अक्टूबर 1977 को काले धन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने कई बार छापेमारी भी की थी। भाजपा सांसद ने सरकारिया आयोग और हजारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बिड़ला समूह ने 1957 से 1977 के बीच कांग्रेस को धन देकर लाइसेंस हासिल किए। उन्होंने कोका-कोला और आईबीएम जैसी विदेशी कंपनियों पर भी कांग्रेस को धन देने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि इन आरोपों से घिरी इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी को तोड़ने के लिए हर तरीका अपनाया। उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राजदूत डेनियल पैट्रिक मोयनिहान की 1978 में प्रकाशित किताब का हवाला देते हुए सीआईए पर कांग्रेस को चंदा देने और विपक्षी दलों को तोड़ने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ, डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने टाली हार



डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल : टेस्ट ड्रॉ होने से न्यूजीलैंड का भारी नुकसान, भारत की राह भी हुई मुश्किल

वेलिंगटन (एजेंसी)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। टेस्ट के पांचवें दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेसिन रिजर्व के मैदान पर टीम की हार को टालने में सफल रहे। टेस्ट मैच के पांचवें दिन ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल की जोड़ी ने 258 गेंदों का सामना करते हुए छठे विकेट के लिए 63 रनों की अटूट साझेदारी निभाई और भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने से रोका। मिचेल 186 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि फिलिप्स 126 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर नाबाद रहे। टेस्ट के पांचवें दिन पहले सेशन में न्यूजीलैंड ने सेट बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (65) का बड़ा विकेट गंवाया। इसके बाद रचिन रविंद्र 129 गेंदों का सामना करने के बाद 37 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टॉम ब्लंडेल ने डेरिल मिचेल के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 102 गेंदों में 37 रन जोड़े।

ब्लंडेल को 15 रनों के स्कोर पर अंशुल कंबोज ने पवेलियन भेजा। हालांकि, इसके बाद मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला और क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े हो गए और उन्होंने दूसरे और फिर तीसरे सेशन में न्यूजीलैंड का एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। भारतीय गेंदबाज आखिरी दो सेशन में सिर्फ एक विकेट चटका सके। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने 120 ओवर तक बल्लेबाजी की और 5 विकेट खोकर 239 रन बनाए। भारत की ओर से दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर एक-एक विकेट ही हासिल कर सके। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए थे।

टीम की ओर से हेनरी निकोल्स ने नाबाद 175 और ग्लेन फिलिप्स ने 118 रनों की शानदार पारी खेली। इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट गंवाकर 720 रन बनाने के बाद अपनी पारी घोषित कर दी।

भारत और न्यूजीलैंड के वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। हालांकि, पहला टेस्ट ड्रॉ होने से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की प्वाइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद न्यूजीलैंड डब्ल्यूटीसी की प्वाइंट्स टेबल में अपना दूसरा स्थान गंवा बैठी है। न्यूजीलैंड को एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है और वह अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है।

इस ड्रॉ से ऑस्ट्रेलिया को जरूर फायदा पहुंचा है और वह एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर आ गई है। न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत अब 66.67 हो गया है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 69.23 है। साउथ अफ्रीका टेबल में पहले स्थान पर बरकरार है और टीम का जीत प्रतिशत 75 है। भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी की प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है। हालांकि, पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम का जीत प्रतिशत अब 50 रह गया है। बांग्लादेश 40.74 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर काबिज है। भारतीय टीम के डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने की राह इस ड्रॉ के साथ मुश्किल हो गई है। अब टीम इंडिया को कुल 6 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिनमें से एक न्यूजीलैंड और पांच मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने हैं। भारत को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए अब अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीतना जरूरी हो गया है।

न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन टेस्ट के पांचवें दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी हार को टाला। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने 43 ओवर बल्लेबाजी की और आखिरी सेशन में न्यूजीलैंड को कोई भी झटका नहीं लगने दिया। न्यूजीलैंड ने टेस्ट के आखिरी दो सेशन में सिर्फ एक विकेट गंवाया। डेरिल मिचेल ने 186 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बनाए और नाबाद रहे, तो फिलिप्स ने 126 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 26 रन बनाए। इससे पहले, फिलिप्स ने पहली पारी में भी 118 रन की शानदार पारी खेली थी।

यह काफी थका देने वाला टेस्ट था, दोनों टीमों ने पूरा जोर लगाया : हेनरी निकोल्स

वेलिंगटन (एजेंसी)



भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेसिन रिजर्व में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे हेनरी निकोल्स ने कहा कि पांच दिनों तक चले इस कड़े मुकाबले ने खिलाड़ियों के शरीर पर काफी असर डाला है और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को कुछ समय तक शरीर में दर्द महसूस होता रहेगा। टेस्ट के पहले दिन जब न्यूजीलैंड का स्कोर 70/5 था, तब निकोल्स ने ग्लेन फिलिप्स (118 रन) के साथ मिलकर टीम को संभाला और नाबाद 175 रन बनाए। इसके बाद जब भारत ने अपनी पहली पारी 720/9 के विशाल स्कोर पर घोषित की, तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को लंबे समय तक फील्डिंग करनी पड़ी।

दूसरी पारी में निकोल्स ने 31 रन बनाए, जबकि डेरिल मिशेल (नाबाद 49) और फिलिप्स (नाबाद 26) ने 258 गेंदों का सामना किया। इससे न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 239/5 के स्कोर तक पहुंचकर मैच को ड्रॉ कराने में सफल रहा। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में निकोल्स ने कहा, यह अच्छा रहा। आपने जैसा कहा कि यह गेंदबाजी वाली पारी भी थी। मगर आज कुछ न करना थोड़ा अजीब लग रहा था, जो कि कभी भी अच्छा नहीं लगता। शरीर में दर्द तो था ही, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर और मैदान पर रहता तो अच्छा होता।

यह वाकई काफी थका देने वाला टेस्ट था और मुझे लगता है कि पांच दिनों के बाद हर कोई इसे जरूर महसूस कर रहा होगा। मैच को याद करते हुए बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि पहले दिन के मुकाबले पिच काफी बदल गई थी। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए मैच बचाने के लिए डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की तारीफ की। हेनरी निकोल्स ने कहा, पांच दिनों के खेल को पीछे मुड़कर देखना दिलचस्प है। पहली पारी से लेकर मैच के अंत तक, विकेट लगातार बदलता रहा। हालांकि, मुझे लगता है कि यह वाकई एक बहुत अच्छा टेस्ट मैच था।

दोनों टीमों ने अपना पूरा जोर लगा दिया और आज खिलाड़ियों को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने बल्लेबाजों के अनुकूल पिच पर भी कड़ी मेहनत की। मगर मुझे लगता है कि हम सभी ने वहां मौजूद चुनौतियों को देखा। इसकी कारण जिस स्थिति में हम थे, वहां से मैच ड्रॉ करा लेना एक सुखद परिणाम रहा।

भारत बनाम न्यूजीलैंड : टीम के प्रदर्शन से गदगद कप्तान टॉम लाथम, बोले- खिलाड़ियों की मेहनत पर गर्व है



वेलिंगटन (एजेंसी)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने टेस्ट के आखिरी दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम की हार को टाला। कीवी कप्तान टॉम लाथम टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए।

पहले टेस्ट का अंत ड्रॉ के रूप में होने के बाद लाथम ने कहा, 'हां, मैं बहुत प्रभावित हूं। पूरे हफ्ते हमारे कुछ खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी उठाई है, खासकर बल्लेबाजी में। मुश्किल हालात में होने के बावजूद, तीसरी पारी में हम जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, उसके बाद मैं काफी खुश हूं। मुझे लगता है कि यही एक टीम का असली चरित्र है कि आप हर बार सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों पर ही निर्भर नहीं रहते। यह खेल ही कुछ ऐसा है जहां हर दिन आपका नहीं हो सकता। मगर जब भी मौका मिलता है, तो हमारे खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। इस टेस्ट मैच में भी कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा ही किया।' पिच को लेकर बात करते हुए लाथम ने कहा, 'शायद यह उतनी सपाट नहीं थी। यह वैसी बेसिन रिजर्व मैदान की विकेट नहीं थी, जिस पर हम आमतौर पर खेलते आए हैं - खासकर पिछले कुछ वर्षों में। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया में आप कहीं भी जाएं - चाहे यहां खेलें या विदेश में - सबसे अहम बात होती है कि आप वहां की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को कैसे ढालते हैं।

'हमें पता था कि इस पिच पर 10 विकेट लेना एक चुनौती होगी', पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद बोले कप्तान शुभमन गिल

वेलिंगटन (एजेंसी)



भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने 43 ओवर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की हार को टाला। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि उन्हें पता था कि बल्लेबाजी के लिए मददगार इस पिच पर 10 विकेट निकालना एक चुनौती होगी।

मैच के बाद कप्तान गिल ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें पता था कि उस पिच पर 10 विकेट लेना एक चुनौती होगी। मगर मुझे लगता है कि हमारे पास मौके थे, बीच-बीच में कुछ मौके मिले, खासकर जब निचले क्रम के बल्लेबाज जल्दी आ गए थे। इस वजह से मुझे लगता है कि फील्ड पर हमारा दिन काफी अच्छा रहा।' टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा, मुझे लगता है कि हमने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। घर से बाहर खेलते हुए हमने उन्हें हर मोर्चे पर चुनौती दी। पहली पारी में जब हम गेंदबाजी करने उतरे, तब भी हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर बल्लेबाजी में भी, सभी ने अपना योगदान दिया। भले ही केवल दो शतक लगे, लेकिन हमने लगभग 700 रन बनाए, जो कि बहुत बड़ी बात है।

शुभमन गिल ने उम्मीद जताई कि वेलिंगटन के मुकाबले क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में गेंदबाजों को विकेट से थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि क्राइस्टचर्च में गेंदबाजों को विकेट से थोड़ी और मदद मिलेगी। इसी वजह से अगर हम वहां भी इसी तरह का खेल दिखा सकें और अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की योजनाओं को लगातार अच्छे से लागू कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी स्थिति में होंगे। उन्होंने मैच ड्रॉ पर खत्म करने के फैसले पर सहमति जताने के अपने फैसले को लेकर कहा, अगर विकेट से थोड़ी और मदद मिलती, तो शायद बात अलग होती, लेकिन तेज गेंदबाज थक चुके थे। उन्होंने इस मैच में लगभग 50-50 ओवर गेंदबाजी की थी।

इसके अलावा, अगला मैच सिर्फ तीन दिन बाद है और कल हमें यात्रा भी करनी है। इसी कारण हम अपने सभी गेंदबाजों को तरोताजा रखना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि 5-10 अतिरिक्त ओवर फेंकने से कोई खास फायदा होता।

सिराज को बाहर रखना मेरे लिए भी मुश्किल फैसला था, मैच से पहले उनसे बात की थी : शुभमन गिल



वेलिंगटन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेसिन रिजर्व में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जुझारू पारियों के दम पर न्यूजीलैंड पहले टेस्ट में हार को टालने में सफल रहा। मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने का कारण बताया। गिल ने कहा, 'हमने इस मैच के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण को मैदान में उतारा। सिराज एक शानदार खिलाड़ी और बेहतरीन गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मगर इन सबसे बढ़कर, वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, भारत के लिए खेलने से पहले से ही हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। इसलिए उन्हें बाहर रखना मेरे लिए भी एक बहुत मुश्किल फैसला था। हालांकि, कभी-कभी आपको यह देखना पड़ता है कि कौन से गेंदबाज फॉर्म में हैं और कौन सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहा है।' दरअसल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा चक्र में मोहम्मद सिराज भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं।

अंत तक लड़े 'शतकवीर' तिलक वर्मा, मगर पाकिस्तान-ए के खिलाफ नहीं दिला सके जीत

दोहा (एजेंसी)



पाकिस्तान-ए ने भारत-ए के खिलाफ रविवार को एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के मुकाबले में 48 रन से जीत हासिल की। वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में तिलक वर्मा ने शतकीय पारी के साथ अपना दमखम दिखाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 'ग्रुप-बी' की प्वाइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तान-ए 49.2 ओवरों में 313 रन पर सिमट गई। शामल हुसैन ने माज सदाकत के साथ पहले विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी की। हुसैन 23 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 33 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम ने 67 के स्कोर पर रोहेल नजीर (0) का विकेट भी गंवा दिया। यहां से हसन नवाज (79) ने मोर्चा संभाला। उन्होंने माज सदाकत (59) के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की, जबकि कप्तान अब्दुल समद (28) के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन जुटाए। इसके अलावा, फरहान यूसुफ के साथ पांचवें विकेट के लिए 44 रन टीम के खाते में जोड़े। पाकिस्तान ने 230 के स्कोर पर अपना पांचवां विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद फरहान यूसुफ ने छोटी-छोटी साझेदारी करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया।

यूसुफ 48 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय खेमे से हर्षित राणा, प्रिंस यादव, सूर्यांश शेडगे और विपराज निगम ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि आयुष बडोनी को 1 विकेट हाथ लगा। इसके जवाब में भारतीय टीम 49.1 ओवरों में 265 रन पर सिमट गई। सलामी जोड़ी के रूप में वैभव सूर्यवंशी ने तिलक वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 25 रन की साझेदारी की। वैभव 13 गेंदों में 2 चौकों के साथ 11 रन बनाकर आउट हुए। टीम के खाते में एक रन और जुड़ा था कि आयुष बडोनी (0) भी अपना विकेट गंवा बैठे। यहां से कप्तान तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जोड़कर टीम को 93 के स्कोर तक पहुंचाया। अभिषेक 42 गेंदों में 6 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 70 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम ने तेजी से विकेट गंवाए। आलम ये रहा कि 25.3 ओवरों के खेल तक भारत ने 129 के स्कोर पर अपना छठा विकेट भी खो दिया।

'नो हैंडशेक' के पीछे बड़े मुद्दे हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं : एमसीसी हेड ऑफ क्रिकेट

शारजाह (एजेंसी)

मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने माना है कि जब राजनीति शामिल हो, तो खिलाड़ियों को हैंडशेक (हाथ मिलाने) से बचने से रोकना उनके बस में नहीं है, भले ही वे 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' (खेल की भावना) को बचाए रखना चाहते हों। क्रिकेट में हैंडशेक न करने का मुद्दा मुख्य रूप से भारत-पाकिस्तान मैचों से जुड़ा है।

अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से टॉस के समय या मैच के बाद पारंपरिक रूप से हाथ मिलाने की प्रक्रिया को छोड़ देना एक आम बात हो गई है। हालांकि हैंडशेक खेल भावना का एक पारंपरिक प्रतीक है, लेकिन आईसीसी के नियमों के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच हैंडशेक न करने के मामले पुरुषों, महिलाओं और विभिन्न आयु वर्गों के मैचों में देखी गई हैं। इसमें रविवार को दोहा में भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच खेला गया एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स मैच भी शामिल है। जब एमसीसी के हेड ऑफ क्रिकेट फ्रेजर स्टीवर्ट से पूछा गया कि क्या खिलाड़ियों के हाथ मिलाने से इनकार करने पर खेल भावना को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बड़े राजनीतिक मुद्दे कहीं अधिक अहम होते हैं और वे उनके नियंत्रण से बाहर हैं। शारजाह में आईएलटी20 के दौरान स्टीवर्ट ने कहा, 'मुझे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो क्रिकेट से परे होती हैं। ये ऐसे स्तर से आती हैं, जहां भू-राजनीतिक मुद्दों पर बात करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने बताया कि एमसीसी तो यही चाहेगा कि खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाएं, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र केवल खेल के दौरान खिलाड़ियों के व्यवहार तक ही सीमित है।

उन्होंने आगे कहा, 'हम केवल मैदान पर होने वाली चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे खिलाड़ी एक-दूसरे का सम्मान करें, अंपायरों और उनके फैसलों का सम्मान करें, और खेल का सम्मान करें। बस इतना ही हमारे नियंत्रण में है। स्टीवर्ट ने आगे कहा कि अगर नेताओं या उच्च स्तर से खिलाड़ियों को हाथ न मिलाने का आदेश दिया जाता है, तो एमसीसी इसमें दखल देकर उसे बदल नहीं सकता। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर ऊपर से हैंडशेक न करने के आदेश आते हैं, तो एमसीसी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। हम तो यही चाहेंगे कि खिलाड़ी हाथ मिलाएं, लेकिन हम समझते हैं कि इसके पीछे बड़े मुद्दे हैं, जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं।

हाथ में फ्रैक्चर के कारण जैक्स लौटेंगे इंग्लैंड, टॉम संभालेंगे उपकप्तानी

मेलबर्न (एजेंसी)



इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स हाथ में फ्रैक्चर के कारण ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में टॉम बैंटन को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। वहीं, पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम में एक नए खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है। जैक्स को मेलबर्न में पहले टी20 मुकाबले में मिली करीबी हार के दौरान चोट लगी थी। अपनी टीम की पारी के 19वें ओवर में बेन ड्वारशुइस की गेंद पर मुश्किल कैच पकड़ने की कोशिश में उनके दाएं हाथ में चोट लग गई। इसके बाद उनके हाथ से खून बहने लगा और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। जांच में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें स्वदेश लौटना पड़ रहा है। उनके साथी खिलाड़ी गोल्ड कोस्ट के लिए रवाना हो गए हैं। चोट के कारण जैक्स पहली बार अपने देश की कप्तानी करने का मौका भी गंवा देंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से पहले पांचवां और अंतिम टी20 मुकाबला खेला जाना है। नियमित कप्तान हैरी ब्रूक इस मैच में उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में जैक्स को दो दिसंबर को कैनबरा में होने वाले मुकाबले में टीम की कमान सौंपने की योजना थी। अब यह जिम्मेदारी बैंटन को दी गई है। उन्हें अधिक अनुभवी खिलाड़ियों से आगे चुनकर ब्रूक का उपकप्तान बनाया गया है। इस दौड़ में फिल सॉल्ट और सैम करन भी शामिल थे। सॉल्ट 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके हैं, जबकि सैम करन इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स और वाइटैलिटी ब्लास्ट में सरे की कप्तानी कर चुके हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद से बैंटन ने कोचिंग स्टाफ को प्रभावित किया है। उन्होंने टीम में शांत लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाई है और जैकब बेथेल तथा जोस बटलर की चोटों के कारण मिले अवसरों का पूरा फायदा उठाया है। तेज गेंदबाज स्कॉट करी भी कैनबरा में दो दिसंबर को होने वाले पांचवें टी20 मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम से जुड़ेंगे। लंबे कद के दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अब तक इंग्लैंड के लिए तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं।

डेविड बेकहम ने 'बाल विवाह' के खिलाफ आवाज उठाने वाली झाबुआ की आदिवासी किशोरी को सराहा

भोपाल (एजेंसी)



इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान और यूनिसेफ के गुडविल एंबेसडर डेविड बेकहम ने मध्य प्रदेश के झाबुआ की एक आदिवासी किशोरी हिमा के असाधारण साहस और हिम्मत को सराहा है। उनकी इस तारीफ के बाद झाबुआ की यह किशोरी चर्चा का विषय बन गई है और लोग उसके साहस की प्रशंसा कर रहे हैं। दिग्गज फुटबॉलर ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, 'यूनिसेफ के साथ पिछले 20 वर्षों के काम के दौरान, मैंने देखा है कि सही समर्थन मिलने पर लड़कियां कैसे नेतृत्व कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। 'विश्व बाल दिवस' के मौके पर, मैं भारत के मध्य प्रदेश की 17 वर्षीय हिमा की कहानी साझा कर रहा हूं, जिन्होंने अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद से बहादुरी से अपना बाल विवाह रुकवा दिया। अब वह भी अपने शिक्षकों के नक्शेकदम पर चलकर दूसरी लड़कियों को अपना भविष्य संवारने में मदद करने का सपना देखती हैं। यूनिसेफ और उसके सहयोगियों के जमीनी स्तर पर किए गए काम के बिना ऐसी कहानियां संभव नहीं हो पातीं। 'इस 'विश्व बाल दिवस' पर और हमेशा, हमें दुनिया भर के युवाओं का समर्थन करते रहना चाहिए, ताकि उनकी तरक्की किस्मत के भरोसे न रहे। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और फंड में कटौती जैसी चीजें तरक्की के लिए खतरा हैं, लेकिन आगे क्या होगा, यह हमारे सामूहिक फैसलों पर निर्भर करता है।

वर्दी पहनना चाहती थीं सेलिना जेटली, किस्मत ने पहना दिया फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज



अभिनेत्री सेलिना जेटली आज किसी कॉकपिट में बैठकर बादलों के बीच उड़ान भर रही होतीं या किसी अस्पताल के गलियारों में तेज कदमों से चल रही होतीं, तो शायद किसी को हैरानी न होती क्योंकि अभिनय की दुनिया में आने से पहले वह भारतीय वायुसेना की पायलट या डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया और वे बॉलीवुड की हीरोइन बन गईं। आइए जानते हैं कि सेना की वर्दी पहनने की चाह रखने वाली वाली एक साधारण सी लड़की ने कैसे ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा और बॉलीवुड की अदाकारा के तौर पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। 24 नवंबर 1981 में हिमाचल प्रदेश में जन्मी अभिनेत्री सेलिना जेटली बॉलीवुड की उन अदाकारों में शुमार हैं, जिनका परिवार पीढ़ियों से देश की सेवा में योगदान देता आ रहा है। दरअसल, अभिनेत्री के पिता भारतीय सेना (कुमाऊं रेजिमेंट) में कर्नल थे और साल 1971 में भारत-पाक युद्ध में हिस्सा भी लिया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी सुनने की शक्ति चली गई थी। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भी सेवा दी थी और उनकी मां मीता सेना में नर्स रह चुकी हैं। उनके नाना भी भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स में कर्नल के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने 1962 व 1965 के युद्धों में भाग लिया था। वीरता के लिए उन्हें सेनाध्यक्ष (सीओएएस) प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में वे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हिरासत में लिए जाने के मामले को लेकर चर्चा में रहे हैं। माता- पिता के तबादलों के चलते अभिनेत्री सेलिना जेटली का बचपन देश के अलग-अलग हिस्सों में बीता, जिससे उन्हें कई भाषाओं और परिवेशों को समझने का मौका मिला। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद अभिनेत्री ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य (कॉमर्स) में स्नातक किया। आर्मी के माहौल में पली-बढ़ी सेलिना बचपन में अपने पिता की तरह सेना में शामिल होना चाहती थीं, उन्होंने मन बना लिया था कि वह पायलट और डॉक्टर बनेंगी। **(एजेंसी)**

आकांक्षा पुरी ने बताया इंडस्ट्री में टिके रहने का मंत्र, बोलीं- 'वक्त के साथ नहीं बदले तो कोई और आपकी जगह ले लेगा'

अभिनेत्री आकांक्षा पुरी मनोरंजन जगत में पिछले 14 साल से सक्रिय हैं। उन्होंने तमिल फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और हिंदी सिनेमा, टेलीविजन और अब ओटीटी तक का सफर तय किया है। इस दौरान उन्होंने खुद को वक्त के साथ ढाला और नए मौकों के अनुसार अपने काम करने का तरीका भी बेहतर किया। अभिनेत्री का कहना है कि इंडस्ट्री में लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करने के साथ बदलाव को अपनाना भी जरूरी है। अगर कोई कलाकार समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करता, तो उसकी जगह कोई दूसरा ले सकता है। टीसीईएल 2027 के मौके पर बातचीत में आकांक्षा ने इंडस्ट्री में बने रहने का अपना मंत्र साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक कलाकार को लगातार खुद पर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ अभिनय से लेकर मेकअप और हेयरस्टाइल तक बहुत कुछ बदल जाता है। आकांक्षा ने कहा, ''मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी ही सबसे जरूरी है। आपको लगातार खुद पर काम करते रहना चाहिए। मैं पिछले 14 साल से इंडस्ट्री में हूं, लेकिन 13-14 साल पहले जिस तरह का मेकअप और हेयरस्टाइल होता था या जिस तरह की एक्टिंग होती थी, वह आज काम नहीं करती। आज सोशल मीडिया है। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना होगा और हर बदलाव को खुले दिल से अपनाना होगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। हमने भी यही किया। खुद को अपडेट किया, अपने ऊपर काम जारी रखा और हर बदलाव को स्वीकार किया।'' अभिनेत्री ने बातचीत में अपने करियर के अलग-अलग पड़ावों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनका सफर किसी एक इंडस्ट्री या प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने साउथ फिल्मों से शुरुआत की, फिर हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में काम किया और अब ओटीटी पर भी अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा, ''आज मैं ओटीटी पर काम कर रही हूं। इससे पहले मैं टेलीविजन पर काम कर रही थी और उससे पहले साउथ में काम कर रही थी। इसलिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि समय बदल रहा है। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे, तो आपकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। मैं लगातार खुद पर काम करती हूं और बदलाव को स्वीकार करती हूं। यही चीज मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।'' आकांक्षा के फिल्मी सफर की बात करें, तो उन्होंने साल 2013 में तमिल फिल्म 'एलेक्स पांडियन' से अभिनय की शुरुआत की थी। **(एजेंसी)**





बिग बॉस 20 : अरिश्फा का सालों पुराना सपना पूरा करेंगे सलमान, काजी तौकीर को भी दिया काम का ऑफर

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। शो के हालिया एपिसोड में सलमान की अरिश्फा खान और काजी तौकीर के साथ खास बातचीत देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अरिश्फा के साथ हंसी-मजाक किया, बल्कि उनके सालों पुराने सपने को पूरा करने का वादा भी किया। वहीं, सलमान ने काजी तौकीर को भी शो से बाहर आने के बाद अपने साथ काम करने का मौका देने की बात कही। दरअसल, 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार एपिसोड में अरिश्फा खान ने सलमान के लिए अपनी दीवानगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि सलमान के साथ काम करना उनका कई साल पुराना सपना है। इस बीच उन्होंने बचपन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुनाया। अरिश्फा ने बताया कि बचपन में वह सलमान से शादी करने का सपना लेकर मुंबई आई थीं, क्योंकि वह उनके बचपन के क्रश रहे हैं। इसके बाद अरिश्फा ने सलमान से पूछा, 'क्या मुझे कभी आपके साथ काम करने का मौका मिल सकता है?' इस पर सलमान ने कहा, 'मैं आपका यह सपना जरूर पूरा करूंगा।' इसके बाद सलमान उनकी आवाज़ और उनके बेबाक अंदाज़ को लेकर भी मस्ती करते दिखे। एक मौके पर अरिश्फा ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें उनकी बातें सुनना पसंद है या फिर लगातार बोलते रहने से कभी उन्हें चिढ़ होती है? इस पर सलमान ने उन्हें 'एडोरेबल' बताया। अरिश्फा के साथ मस्ती करने के बाद सलमान ने शो के कंटेस्टेंट काजी तौकीर की तरफ रुख किया। काजी शो में कई बार अपनी सिंगिंग का हुनर दिखा चुके हैं। उनकी आवाज और गाने के अंदाज को देखते हुए सलमान ने उन्हें एक खास ऑफर दिया। उन्होंने काजी से कहा, 'काजी, जब तुम शो से बाहर आओगे, तो मैं तुम्हें एक गाना दूंगा।' सलमान की यह बात सुनकर काजी काफी खुश हो गए और उन्होंने सुपरस्टार का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि पहले भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को सलमान के साथ काम करने का मौका मिला है। इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम शहनाज गिल का है। 'बिग बॉस 13' की सबसे लोकप्रिय कंटेस्टेंट्स में से एक शहनाज को सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में काम करने का मौका मिला। वहीं, 'बिग बॉस 6' की कंटेस्टेंट सना खान ने सलमान के साथ फिल्म 'जय हो' में काम किया था। इसी सीजन के कंटेस्टेंट संतोष शुक्ला भी 'जय हो' और 'दबंग' में नजर आए थे। वहीं, 'बिग बॉस 7' का हिस्सा रहे अरमान कोहली बाद में फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में दिखाई दिए। दूसरी तरफ, 'बिग बॉस 9' में नजर आईं नोरा फतेही को भी सलमान के साथ फिल्म 'भारत' में काम करने का मौका मिला। **(एजेंसी)**



शोभिता धुलिपाला : नागा चैतन्य के 40वें जन्मदिन पर पत्नी ने लुटाया प्यार, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

साउथ सिनेमा के चर्चित कपल शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को निजी रखना पसंद करते हैं। दोनों सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के साथ कम ही तस्वीरें साझा करते हैं। हालांकि, खास मौकों पर उनका प्यार जाहिर करने का अंदाज फैंस का ध्यान खींच लेता है। अब नागा चैतन्य के 40वें जन्मदिन पर पत्नी शोभिता ने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पति के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। शोभिता ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर नागा चैतन्य के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं। माना जा रहा है कि यह तस्वीर साइप्रस में दोनों की छुट्टियों के दौरान की है। फोटो में अभिनेत्री ब्लैक कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। वहीं, अभिनेता लाल कलर की टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहने दिखे। पहली तस्वीर में कपल एक-दूसरे को किस कर रहा है, दूसरी पोस्ट में नागा चैतन्य की एक वीडियो है और तीसरी तस्वीर में दोनों पोज देकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं। इसे शेयर करते हुए शोभिता ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे लवर'। बता दें कि नागा चैतन्य अपनी आने वाली फिल्म 'वृषकर्मा' के प्रमोशन के दौरान पत्नी के बारे में बात करते नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने शोभिता को 'माय लव' कहकर संबोधित किया था। अभिनेता का यह अंदाज उनके रिश्ते की एक खूबसूरत झलक दिखाता है। शोभिता और नागा चैतन्य के रिश्ते को लेकर साल 2022 से ही चर्चाएं शुरू हो गई थीं, लेकिन दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा। नागा चैतन्य ने जगपति बाबू के टॉक शो 'जयम्मु निश्चयम्मुरा' में अपनी प्रेम कहानी से जुड़ा दिलचस्प खुलासा किया था। **(एजेंसी)**

भारत में गरीबी को बनाए रखने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में आया बुनियादी बदलाव : वित्त मंत्री सीतारमण

नई दिल्ली (एजेंसी)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अस्थायी राहत देने के बजाय गरीबी को बनाए रखने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में बुनियादी बदलाव आया है।

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए, जिसमें बताया गया है कि 2011 से 2023 के बीच करीब 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं और अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो गई है, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये आंकड़े उस बदलाव को दर्शाते हैं, जिसे उन्होंने 'खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है।' वित्त मंत्री सीतारमण ने लिंकडइन पर प्रकाशित एक लेख में कहा, प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अस्थायी राहत देने के बजाय गरीबी को बनाए रखने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में बुनियादी बदलाव आया है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए, जिसमें बताया गया है कि 2011 से 2023 के बीच करीब 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं और अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो गई है, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये आंकड़े उस बदलाव को दर्शाते हैं, जिसे उन्होंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है



ने कहा है कि आजादी की तरह ही विकसित भारत एक ऐसा संकल्प है जिसे हर भारतीय को जीना है। छह दशकों तक अधूरे रहे लक्ष्य को हमने दस वर्षों में हासिल किया है। भारत अब अगले बीस वर्षों की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकता है। 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प के साथ 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमारी पहुंच में है और हम सब मिलकर इसे हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद छह दशकों से अधिक समय तक व्यापक गरीबी को खत्म करना एक अधूरा वादा बना रहा। वित्त मंत्री ने कहा,2010 के शुरुआती वर्षों में भी विदेशों में भारत को लंबे समय से चली आ रही गरीबी का केंद्र बताया जाता था।

स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ ईंधन और बैंकिंग सुविधाओं के मामले में भारत पिछड़ा हुआ माना जाता था। उस समय यह धारणा थी कि गरीबों के हाथों में पैसा दे दिया जाए तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस सोच को बदल दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि अंत्योदय यानी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण के सिद्धांत से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने घर-घर जाकर अभावों को दूर करने का कठिन रास्ता चुना, ताकि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने हर योजना को उन लोगों पर केंद्रित किया जिन्हें उसकी जरूरत थी। योजनाओं का लक्ष्य मापने योग्य परिणाम हासिल करना और उन अभावों को दूर करना था, जिनके लिए उन्हें शुरू किया गया था। इसके लिए कोई जादुई छड़ी नहीं थी। प्रत्येक योजना के तहत लाभार्थियों की सही पहचान, प्रभावी वितरण और अंतिम परिवार तक लाभ पहुंचने तक निगरानी सुनिश्चित करनी पड़ी।

टाटा स्टील ट्यूब और पाइप कारोबार, टाटा स्टील कलर्स को 28,000 करोड़ रुपये में बेचेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)

टाटा स्टील के निदेशक मंडल ने रविवार को कंपनी के स्टील ट्यूब और पाइप कारोबार के साथ ही टाटा स्टील कलर्स प्राइवेट लिमिटेड (टीएससीएल) को एपीएल अपोलो ट्यूब्स को बेचने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन दोनों सौदों का कुल मूल्य करीब 28,000 करोड़ रुपये है। टाटा स्टील ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि स्टील ट्यूब और पाइप कारोबार को 11,700 करोड़ रुपये तक में बेचने और टाटा स्टील कलर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी 16,300 करोड़ रुपये में एपीएल अपोलो को



बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कंपनी ने बताया कि निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसले किए गए।

निदेशक मंडल ने कंपनी के ट्यूब कारोबार के हस्तांतरण और इस संबंध में एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के साथ कारोबार हस्तांतरण समझौता करने को मंजूरी दी। इस सौदे के तहत जमशेदपुर, होसुर, खोपोली और साहिबाबाद स्थित कंपनी की स्टील ट्यूब विनिर्माण इकाइयों में स्टील ट्यूब और पाइप के विनिर्माण, प्रसंस्करण, विपणन, बिक्री और वितरण का कारोबार एपीएल अपोलो को हस्तांतरित किया जाएगा। यह कारोबार एकमुश्त बिक्री के आधार पर 11,700 करोड़ रुपये तक के भुगतान पर हस्तांतरित किया जाएगा। निदेशक मंडल ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी टाटा स्टील कलर्स प्राइवेट लिमिटेड (टीएससीएल) में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी एपीएल अपोलो को 16,300 करोड़ रुपये में बेचने और हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी।

पायलट संघ ने स्पाइसजेट की वित्तीय और सुरक्षा जांच की मांग की

नई दिल्ली (एजेंसी)

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने रविवार को विमानन नियामक डीजीसीए से संकट से जूझ रही स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का तत्काल आकलन करने की मांग की। संघ ने यह भी कहा कि एयरलाइन की वित्तीय मुश्किलों का कर्मचारियों, विशेषकर चालक दल के सदस्यों के कल्याण और कामकाज पर पड़ने वाले असर की जांच की जानी चाहिए।

एफआईपी ने नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू को लिखे पत्र में स्पाइसजेट के मामले में मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उसने सभी नियमित विमानन कंपनियों की



वित्तीय स्थिति की सालाना व्यापक समीक्षा करने का भी सुझाव दिया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 17 नवंबर को स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी कर उड़ानों के रद्द होने की बढ़ती संख्या, भुगतान में देरी के कारण परिचालन में आ रही बाधाओं और कुछ नियमों के उल्लंघन पर विस्तृत जवाब मांगा था। एयरलाइन को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। एफआईपी ने रविवार को पत्र में कहा, 'हमारा विशेष सुझाव है कि प्रत्येक नियमित एयरलाइन कंपनी की वित्तीय स्थिति और सुरक्षा जोखिम का अनिवार्य रूप से सालाना आकलन किया जाए। वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनियों की तिमाही आधार पर निगरानी भी की जानी चाहिए।'

स्पाइसजेट के संबंध में पायलट संघ ने एयरलाइन की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस), चालक दल के सदस्यों की थकान से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी देने के माहौल का आकलन करने की मांग की है। पत्र में यह भी कहा गया है कि नौकरी की असुरक्षा या आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारी थकान, परिचालन संबंधी समस्याओं या सुरक्षा में खामियों की जानकारी देने से बच सकते हैं।

उन्हें डर हो सकता है कि ऐसा करने पर उनके रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। एफआईपी ने कहा, सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी बिना किसी डर या दबाव के अपनी चिंताएं सामने रख सकें। डीजीसीए को यह आकलन करना चाहिए कि वित्तीय संकट का किसी एयरलाइन के कर्मचारियों, चालक दल के कल्याण, रखरखाव मानकों और समग्र सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर क्या असर पड़ रहा है।